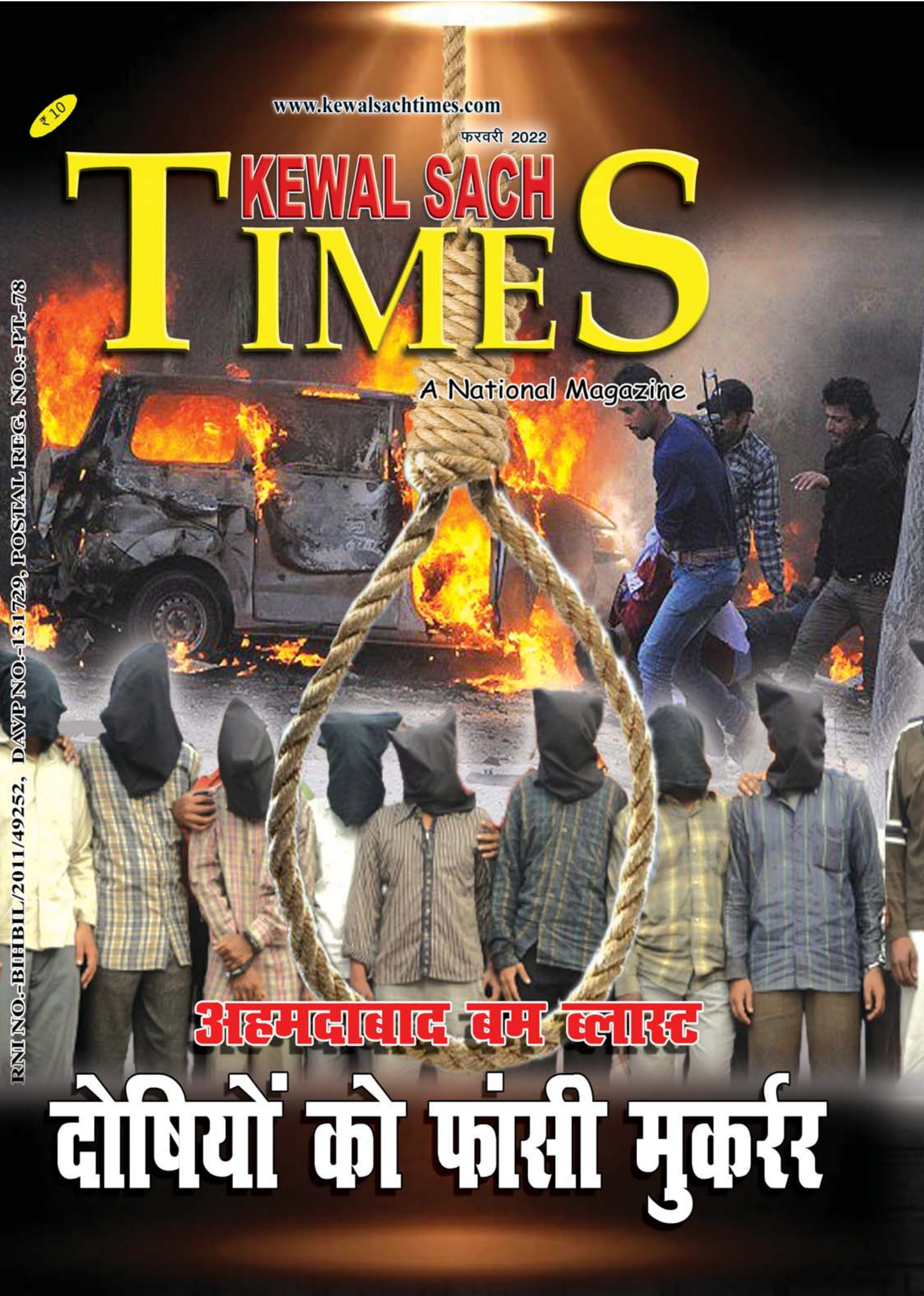

₹ 10
www.kewalsachtimes.com
फरवरी 2022
KEWAL SACH
TIMES
A National Magazine
RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT-78
अहमदाबाद बम ब्लास्ट
दोषियों को फांसी मुकर्रर

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीक हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

जैकी श्रॉफ
01 फरवरी 1960

मनोज तिवारी
01 फरवरी 1971

ब्रह्मनंदम
01 फरवरी 1956

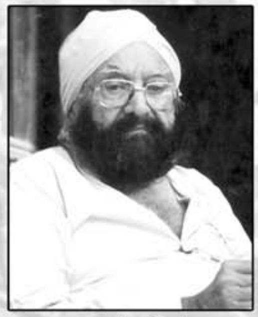
खुशवंत सिंह
02 फरवरी 1915

शमीता शेट्टी
02 फरवरी 1979

रघुराम राजन
03 फरवरी 1963

उर्मिला मांदोडकर
04 फरवरी 1974

अभिषेक बच्चन
05 फरवरी 1976

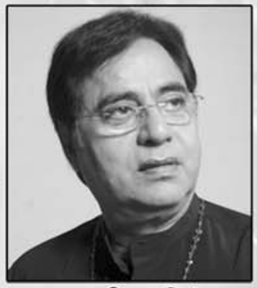
जगजीत सिंह
08 फरवरी 1941

मो० अजहरूद्दीन
08 फरवरी 1963

राहुल रॉय
09 फरवरी 1968

उदिता गोस्वामी
09 फरवरी 1984

कुमार विश्वास
10 फरवरी 1970

चौधरी अजीत सिंह
12 फरवरी 1939

स्व० सुषमा स्वराज
14 फरवरी 1952

टेकलाल महतो
15 फरवरी 1945

रणधीर कपूर
15 फरवरी 1947

प्रफुल्ल पटेल
17 फरवरी 1957

स्व० जयललिता जयराम
24 फरवरी 1948

शाहीद कपूर
25 फरवरी 1981

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-
B & W	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

तनाव एवं समस्या के बीच
अमृत काल

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

India यानि की भारत और हिन्दुओं के लिए हिन्दुस्तान अब PM मोदी के नेतृत्व में अमृत काल में जी रहा है, भले ही Indian PM मोदी के इस शब्दावली प्रयास को नहीं स्वीकार करे परन्तु भाजपा शासित एवं हिन्दुस्तान के राज्यों में अृमत काल चल रहा है इससे इंकार करना विपक्षी होने का सबूत पेश करता है। गरीबी, लाचारी, बेरोजगरी, महंगाई और भ्रष्टाचार अृमतकाल की धरोहर है क्योंकि अब आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और परिवारवाद के बाद राजनीतिवाद के दौर में सोसल मीडिया तय करने लगी है की कौन सा काल चल रहा है जबकि धर्मशास्त्र के अनुसार कलियुग चल रहा है परन्तु राजनेताओं की नजरों में अृमतकाल है और स्वाभाविक बात है की नेता जी को खुश रखने के लिए जहर पीने के बाद भी अृमत महसूस हो रहा है कहना ही होगा। जिस देश में आज भी हर - घर शौचालय बन रहा है यह अमृत काल नहीं तो और क्या है? 105 रूपये लीटर पेट्रोल एवं 1000 में गैस सिलेण्डर 200 रूपये सरसो का तेल खरीद कर भी आपको महंगाई का एहसास नहीं हो यही तो है अमृत महोत्सव का प्रभाव और इस सुशासन में बेरोजगार युवाओं के शरीर पर चमड़ी उधेड़ती पुलिस की प्यार भरी लाठियों की आप आलोचना करेंगे तो यह विपक्षी होने का जीता-जागता प्रमाण है। ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट अगर पकौड़ा तलकर जीवन यापन कर रहे हैं तो क्या यह रोजगार नहीं कहलायेगा? सरकार या किसी राजनीतिक दल ने तो यह कभी नहीं अपने घोषणा-पत्र में लिखा है कि आप शिक्षित होंगे तो सरकारी नौकरी ही देंगे? नेता यह जान चुके हैं कि चुनाव के वक्त सरकारी नौकरी की बात करनी है और सरकार बनने के बाद अगले चुनाव में भी इस मुद्दा को जिवंत रखना है तो फॉर्म भरवाकर 05 साल निकाल लेना है और इस बार हम सत्ता में आये तो सरकारी नौकरी पक्की, भले ही आपका उम्र पार कर जाये तो इसमें सरकार की क्या गलती है। इस विचार को अमृत समझकर पीने में ही भलाई है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं का नारा में अृमत का एहसास तो हो ही रहा है और अब किसी की बेटी गैंग रेपिस्ट की चपेट में आ गयी तो भला इसमें सरकार का क्या दोष, उसमें तो सुशासन है का दाव कर रही है तो देर-सवेर बलात्कारी-अपराधी पकड़ें जायेंगे इतना सार्थक प्रयास करना अमृत काल से कम है या? अब कोई बेटी का बाप खुद ही जज की जगह फैसला लेने लगे तो यह तो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, अब जज साहेब 10 साल में ही सजा सुनायेंगे तो क्या परेशानी है, सच को सामने आने में 10 साल तो लगता हीं है। अब तेलांगना पुलिस का जमीर जागृत हो गया और प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों को इंकाउंटर में मार दिया यह अलग बात है। विभाग एवं मंत्रालय में लाइजनर पदाधिकारियों को 1000 करोड़ का मालिक बना देते हैं काम के बदले कमीशन देकर और आमजनता सबकुछ जानने के बाद भी अमृत का एहसास कर रही है ऐसे में भारत देश में अमृत महोत्सव मनाना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भाजपा एवं उसके समर्थकों के लिए आजदी के 75 वर्ष का अवसर अमृत काल है तो विपक्ष इसको तानाशाही काल से नवाज रहा है और तो और सभी सरकारी उपक्रम को नीजी बनाने का प्रयास को ही अमृत काल कहा जाता है तो वास्तव में इसके लिए भाजपा की सरकार बधाई की पात्र है लेकिन सच क्या है यह भाजपा के भीतर नाम नहीं सार्वजनिक करने के शर्त पर बताते हैं कि यह अमृत काल नहीं चाटुकारिता काल चल रहा है और जो जितना बड़ा चम्मच है उतना ही बड़ा अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है और देश के लाल किला पर किसान आन्दोलन के नेता खुल्लेआम झंडा का अपमान कर रहे हैं और शाहिन बाग में पदाधिकारी को खुल्लेआम शहीद कर दिया जाता है यह अृमत काल का ही तो प्रमाण है। साबुन से लेकर भोजन के हर एक समान पर GST लग रहा है और लोग महंगाई के बाद भी जयश्रीराम और अल्ला उ अकबर कर रहे हैं तो इससे सुखद क्षण कब आयेगा। संविदा पर कार्य करने वाले को PF और ESIC नहीं मिल रहा है और कर्मचारी आन्दोलन करेगा तो उसको संविदा से भी हाथ धोना पड़ेगा यह अमृत काल का प्रमाण नहीं तो और क्या है। देश के भीतर का सच तो यही है की दवाई और ऑक्सीजन के लिए लोग पिछले वर्ष 2021 में तड़पते रहे परन्तु 2022 में ही अमृत काल आ गया, इससे ज्यादा विकास कौन और कैसे कर सकता है। विपक्षी दल को सिर्फ सत्ता चाहिए लेकिन आमजनता के समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना और उनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास तब शुरू होगा जब वह सत्ता में आयेंगे, वैसे में इन्हीं कारणों की वजह से सत्ता पक्ष के द्वारा इस काल को अमृत काल कहा जा रहा है और यह सच भी है कि इस देश का विपक्ष का नियत ठीक है और न ही नियत वैसे में आवाम के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है इस बात को समझने के लिए कि यह काल अृमत का है। देश के भीतर निम्न समस्याएं अपने समाधान के लिए कराह रही है और सरकार के पदाकारी इसको दूर करने के लिए खुल्लेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन सरकार अपने सांसद और विधायक से कहीं ज्यादा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारी पर भरोसा है और यही कारण है कि शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार सरकार के अमृत महोत्सव को खुला चुनौती दे रही है और समय रहते इसपर नकेल नहीं कसा गया तो सरकार के लिए यह अमृत काल जनता के बीच जहरीला काल में तब्दील हो जायेगा और राजीतिक दल महोत्सव मनाते रह जायेंगे।

आजादी के 75 साल में जिस देश में हर - घर सरकार द्वारा शौचालय बनाया जा रहा वहां अृमत काल का महोत्सव कैसे मनाया जा सकता है? बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है वहां उत्सव मनाना कहां तक उचित है? जिस देश में आर्थिक स्थिति को कारगर बनाने के लिए सरकार को उपक्रम को बेचना पड़ रहा है वहां का मानव जीवन अृमत पान कैसे करेगा? हर दिन बेटियां किसी की हवश की शिकार बन रही हैं तो किसी न किसी की हत्या आम बात बन चुकी है, वहां सुशासन नहीं है फिर अृमत महोत्सव मनाने की बात लोगों को शब्दों के जाल में फंसाने के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हो और लालकिला पर तिरंगे का अपमान हो रहा है उस देश में अृमत काल का चक्र चल रहा है की बात बेमानी नहीं लगती? एक साल से अधिक समय तक किसान आन्दोलन और छात्रों के आन्दोलन पर जानलेवा हमला जैसा पुलिसिया जुल्म अृमत का प्रमाण है और सरकार देशवासियों को बीच वितरित कर रहा है। जातीय भेदभाव एवं आपसी सौहार्द से तनाव में रहने वाला देश में जब एक जात दूसरे जात से भयभीत हो वहां अृमत महोत्सव से राष्ट्र की एकता सार्थक सिद्ध होगा? दवा का अभाव, भूख एवं गरीबी एवं योजनाओं को लूटने वाले के लिए यह काल अृमत से परिपूर्ण है यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। बैंक में अपना ही पैसा निकालने एवं जमा करने पर टैक्स लगने लगे और तो और नहाने से लेकर धोने तक के प्रोडक्ट पर GST लगना ही तो अृमत काल है। CBI जैसे संगठन और आई टी सेल की विवशता भी अृमत काल में घुटन महसूस कर रहा है, लेकिन राजनीति करने वाले पक्ष के लिए अृमत काल एवं विपक्ष के लिए विषैला काल है।

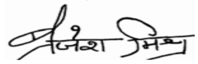

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 11, अंकः- 128 माहः- फरवरी 2022 रू. 10/-

Editor in chief

Brajesh Mishra 09431073769
09955077308
08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 09308815605,
09122003000

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Reeta Singh 9308729879
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 08873004350
S. N. Giri 09308454485

Asst. Editor

Sashi Ranjan Singh 09431253179
Rajeev Kumar Shukla 07488290565

Sub. Editor

Brajesh Sahay 07488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 07762089203

Bureau

Sridhar Pandey 09852168763

Photographer

Mukesh Kumar 0 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 07979769647
07654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 09433567880
09339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 08109932505,
08269322711

छत्तीसगढ़ हेड

डिगल सिंह 09691153103
08982051378

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 09452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

कमोद कुमार कंचन 07492868363

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

श्रवण कुमार चंचल 08977442750

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
रिया प्लाजा, तीसरा तल्ला, कोकर चौक,
राँची (झारखण्ड)
मो०- 9955077308, 9431073769

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 07492868363

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास, बेलभाँटा,
अभनपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो०- 09835845781, 08602674503

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जनवरी 2022

रखैल

मिश्रा जी,

''विज्ञापन के लिए रखैल बन गया है मीडिया'' जनवरी 2022 अंक के केवल सच टाइम्स पत्रिका में पढ़ा तो हैरान हो गया कि स्वयं मीडिया इस बात को स्वीकार कर रही है। पत्रकारिता आसान कार्य नहीं है और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन अपने उपर खबर लिखना वास्तव में सकारात्मक पत्रकारिता का जीता-जागता प्रमाण है। आपका हर अंक का संपादकीय पढ़ता हूं, सरल भाषा में आम आदमी के भीतर के विचारों को आप लिखते हैं। स्पष्ट और बिना लाग-लपेट की खबरों के कारण ही केवल सच टाइम्स पत्रिका का प्रभाव मजबूत होता जा रहा है। सटीक खबर के लिए साधुबाद।

● **मनीष पाठक, चितरंजन कारखाना, पं. बंगाल**

साज सज्जा

संपादक महोदय,

मुझे केवल सच टाइम्स पत्रिका के दिसम्बर 2022 अंक का कवर पेज बहुत ही उत्कृष्ट एवं आकर्षक लगा तथा सभी खबरों का सजावट भी स्तरीय है। अगर यह पत्रिका रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित हो तो इसकी बात ही अलग हो जाती। संपादकीय के साथ-साथ काशी विश्वनाथ धाम और हिन्दू बनाम सिख की खबर और अन्य छोटी बड़ी खबरें भी रोचक एवं जानकारीप्रद लगी। खेल एवं फिल्म को भी पत्रिका में स्थान मिलना चाहिए। कानूनी सलाह की तरह चिकित्सीय सलाह का भी स्थायी स्तंभ होना चाहिए, जिससे पाठकों को एक ही पत्रिका में सबकुछ प्राप्त हो सके। पत्रिका की पूरी टीम को सकारात्मक खबरों के लिए बधाई।

● **कौशल उरांव, कांटाटोली चौक, राँची**

एक पर एक

मिश्रा जी,

''डेटिंग ऐप ने बदल दिये प्यार के मायने'' केवल सच टाइम्स के जनवरी 2022 की खबर में नवीन रांगियाल ने ब्यायफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच का प्यार का खेल का रंग ही उतार दिया है लेकिन सटीक एवं चिंतनीय है। वहीं दूसरी खबर ''पत्नियों की अदला-बदली का घिनौना खेल'' पढ़कर मन काफी व्यथित हुआ की किस प्रकार समाज आज हासिए पर जा रहा है और आनंद की प्राप्ति के लिए किस हद तक गिरता जा रहा है। आपकी पत्रिका कई महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराता है और सच्चाई आवाम के बीच हमेशा लाता है। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है।

● **कन्हैया शर्मा, साकेत बिहार, नई दिल्ली**

हिन्दू बनाम सिख

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका ने जनवरी 2022 अंक में कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल एवं डॉ कृष्णगोपाल मिश्र ने ''हिन्दू बनाम सिख न होने दें'' खबर में हिन्दू एवं सिख धर्म के बीच के संबंधों उसके गौरवशाली इतिहास को बखूबी जनता के बीच रखा है। हिन्दू देह है और हिन्दुत्व उसकी आत्मा है, यह कहना पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। भाषा एवं शब्दों का चयन करना एवं उसको सार्वजनिक पटल पर रखना बहुत ही कठिन कार्य हैं और इसकी सटीक जानकारी रखने वाले विचार दें तो अलग बात है, परन्तु बोलने की आजादी के नाम पर आपसी तनाव का वातावरण बनाया जा रहा है। सटीक खबर लगी।

● **रौशन वर्णवाल, नून का चौराहा, गुलजारबाग**

विश्वनाथ धाम

संपादक महोदय,

अन्य पाठकों की तरह मैं भी केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूं और सभी खबरों को पढ़ता हूं। ललन कुमार प्रसाद की खबर ''काशी विश्वनाथ धाम'' जनवरी 2022 को बहुत ही यादगार बनाता है। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही मायने में संवारने का काम किया है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता की भारतीय संस्कृति के गौरव प्रतीक को जीवंत करके यह सिद्ध कर दिया है की भगवान की नगरी आज भी अपने अवलौकिक इतिहास की साक्षी है। बहुत ही संतुलित एवं जानकारीप्रद खबर लगी। ललन कुमार प्रसाद इस खबर के लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

● **मनोज माँझी, बरही बाजार, हजारीबाग**

पनामा और पैंडोरा

ब्रजेश जी,

जनवरी 2022 अंक में ''क्या है पनामा और पैंडोरा?'' की खबर में जया बच्चन के गुस्से का कारण स्पष्ट तौर पर समझाने में नवीन जैन एवं नवीन रांगियाल कामयाब हैं। टैक्स में चोरी करने का नायाब तरीका अख्तियार करके फिल्म इंडस्ट्रीज को दागदार बनाया गया है। वहीं दूसरी खबर ''होगा वही जो बड़े साहेब चाहेंगे'' में अरबिन्द तिवारी ने मध्यप्रदेश के मामू की व्यथा को लिखा है। इस प्रकार की राजनीतिक खबरें पढ़ने में रोचक तो होती ही है उससे भी अधिक अंदरूनी बातों को आसानी से समझा जा सकता है। जनवरी अंक का हर एक खबर कुछ न कुछ संदेश देता दिख रहा है।

● **पंकज पटेल, रेलवे क्वाटर, भोपाल**

अन्दर के पन्नों में

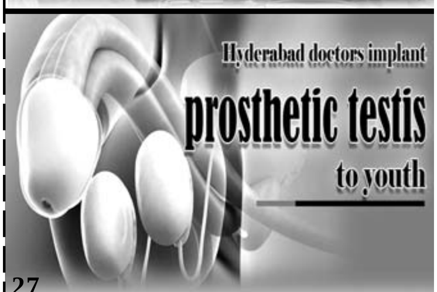

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

देवब्रत्त कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा
" केवल सच " पत्रिका **एवं " केवल सच टाइम्स "**
8986196502/9304877184
devbartkumar15@gmail.com

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **"मगध इंटरनेशनल स्कूल"** टेकारी
" केवल सच " पत्रिका **एवं " केवल सच टाइम्स "**
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, आई. टी. विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी, रालोसपा	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग,पटना-800020(बिहार)
e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
☞ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
☞ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
☞ सभी पद अवैतनिक हैं।
☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 20001817444
BANK :- State Bank Of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

अहमदाबाद बम ब्लास्ट
दोषियों को फांसी मुकर्रर

भारत के न्यायिक इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ है कि किसी एक मामले में एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हालांकि राजीव गांधी हत्या कांड में 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 38 लोगों को फांसी की यह सजा अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने सुनाई है। बता दें कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषियों को यह सजा सुनाई गई है। 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कहा जाता है कि गोधरा कांड के दौरान हुए दंगों का बदला लेने के लिए अहमदाबाद को टारगेट कर के ये ब्लास्ट किए गए थे। ये मामला पिछले 14 सालों से कोर्ट में चल रहा था। अब इसका फैसला 38 लोगों को फांसी देने के साथ आया है। इसी माह के 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को UAPA के तहत दोषी करार दिया। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया जा चुका है। इसके अलावा 29 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। गौरतलब हो कि ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों ने किए थे। विस्फोट से कुछ मिनट पहले, टेलीविजन चैनलों और मीडिया को एक ई-मेल मिला था, जिसे कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन ने धमाकों की चेतावनी दी थी। पुलिस का मानना था कि आईएम के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये ब्लास्ट किए थे। विदित हो कि कुछ इसी तरह का एक साथ 26 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने का फैसला राजीव गांधी हत्याकांड में दिया गया था। 28 जनवरी 1998 को स्पेशल टाडा कोर्ट ने सभी 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान करीब 1 हजार गवाहों के लिखित बयान दर्ज हुए थे। 288 गवाहों से अदालत में जिरह हुई। 10 हजार से ज्यादा पन्नों के 1477 दस्तावेज अदालत में जमा किए गए। प्रस्तुत है अमित कुमार की रिपोर्ट :-

26 जुलाई, 2008 को, लगभग 70 मिनट के अंतराल में, अहमदाबाद शहर में विभिन्न स्थानों पर 22 बम विस्फोट हुए, जिनमें गुजरात सरकार द्वारा संचालित अहमदाबाद सिविल अस्पताल, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एलजी अस्पताल, बसों में, कारों में, खड़ी साइकिल पर भी शामिल थे। इस विस्फोट में 26 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हो गए। वही कलोल और नरोदा में लगाए गए दो बम नहीं फटे। मई में जयपुर और एक दिन पहले बेंगलुरु के बाद अहमदाबाद उस वर्ष बमबारी करने वाला तीसरा शहर था। कुछ मीडिया घरानों को भेजे गए ईमेल में, इंडियन मुजाहिदीन (आईएम), एक संगठन जिसे तब तक नहीं सुना गया था, ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि 27 जुलाई को सूरत में भी इसी तरह के बम मिले थे। इनमें से पहला एक सफाई कामदार को मिला, जो इसे रेडियो समझकर घर ले गया। वही 9 अगस्त तक, शहर में कुल 29 जीवित बम बरामद किए गए थे। वही 2010 और 2011 में, पुणे की जर्मन बेकरी और मुंबई में क्रमशः विस्फोट हुए, जिसमें ANFO (अमोनियम नाइट्रेट) और RDX का उपयोग किया गया था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने बाद में साबरमती सेंट्रल जेल में 2008 के अहमदाबाद विस्फोटों के कुछ आरोपियों से पूछताछ की थी ताकि बाद के हमलों में उनके संबंध या संलिप्तता को स्थापित किया जा सके।

अब 2008 के अहमदाबाद बम हमले में भारतीय अदालत ने 38 को मौत की सजा सुनाई और 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई

है। ज्ञात हो कि 16 समकालिक विस्फोटों ने पश्चिमी राज्य गुजरात को बुरी तरह से हिला दिया था, जहां माना जाता है कि 2002 में हिंदू-मुस्लिम दंगों में हजारों लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। उक्त विस्फोट के लिए इंडियन मुजाहिदीन नामक एक समूह ने 26 जुलाई, 2008 को हुए विस्फोटों की जिम्मेदारी ली थी। न्यायाधीश ए. आर. पटेल ने अभियोजन पक्ष द्वारा मौत की सजा के लिए दबाव डालने के बाद सजा का आदेश दिया। इस घटना को दुर्लभ से दुर्लभ मामला बताया गया है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। 18 फरवरी को अहमदाबाद, भारत में सत्र न्यायालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बचाव पक्ष के एक वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। बता दें कि खालिद शेख ने बताया कि हमने दोषियों के लिए नरम सजा की मांग की थी, क्योंकि वे पहले ही 13 साल से अधिक जेल में बिता चुके हैं। लेकिन अदालत ने उनमें से अधिकांश को मौत की सजा सुनाई। हम निश्चित रूप से अपील के लिए जाएंगे। वही अमेरिकी विदेश विभाग ने 2011 में कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन के पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे और 2005 के बाद से पूरे भारत में दर्जनों बम हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है और सुविधाजनक भूमिका निभाई है। 2008 के मुंबई हमलों में 160 से

अधिक लोग मारे गए थे।

गौरतलब हो कि कथित तौर पर आईएम द्वारा भेजे गए ईमेल में 2002 के गुजरात दंगों की छवियां थीं, और दावा किया कि बम विस्फोट दंगों और 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विनाश का बदला था। इनमें कुल मिलाकर 35 मामले दर्ज किए गए, 20 अहमदाबाद में और बाकी सूरत में और मुकदमा अप्रैल 2010 में शुरू हुआ। अगले सात वर्षों में, विभिन्न राज्यों से 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच ने निष्कर्ष निकाला कि आईएम प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का एक समूह था। अहमदाबाद में जितने भी बम धमाके हुए, उनमें उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल (एएनएफओ) का घातक कॉकटेल था। सनद् रहे कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अलावा आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने जांच का नेतृत्व किया। डीजीपी आशीष भाटिया, जो उस समय अहमदाबाद के डीसीबी में जेसीपी थे, जांच में एक प्रमुख अधिकारी थे। भाटिया के मुताबिक, 15 अगस्त 2008 से पहले 11 लोगों की गिरफ्तारी के साथ इस मामले को सुलझा लिया गया था।

भाटिया ने कहा कि बम पुणे और मुंबई से चुराई गई कारों में रखे गए थे, कारों में गैस सिलेंडर रखे गए थे और बमों को बॉल बेयरिंग से तैयार किया गया था। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक की पुलिस ने कई शहरों में जांच का समन्वय

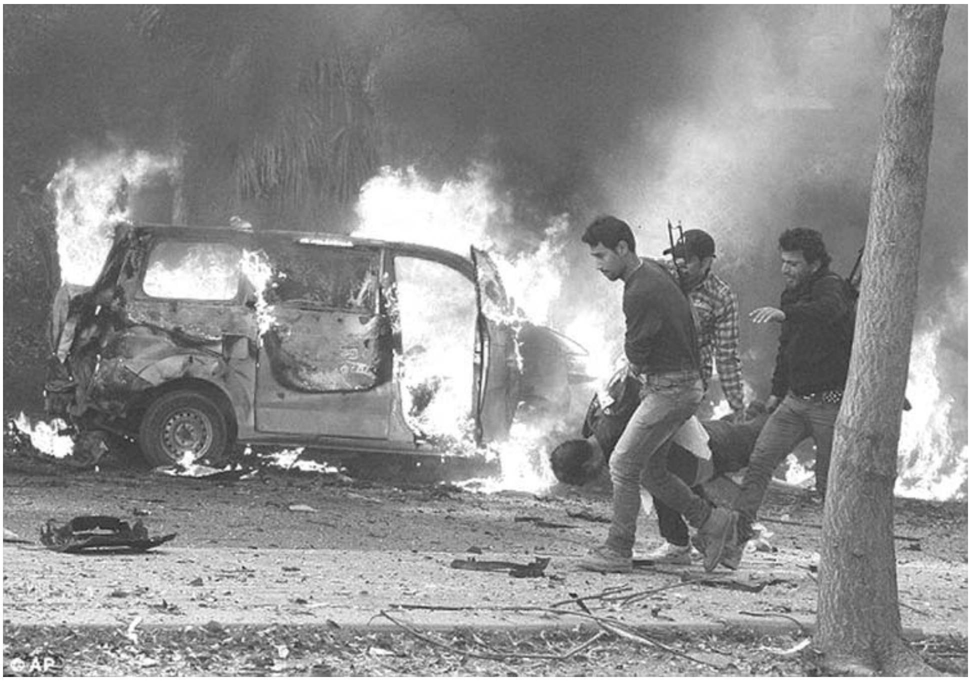

किया, जिसमें एएनएफओ और आईएम के जिम्मेदारी के दावे का सामान्य धागा था। विशेष न्यायाधीश ए.आर. पटेल ने सीआरपीसी की धारा 268 के तहत उन आरोपियों को अपना फैसला सुनाया, जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले विचाराधीन कैदियों पर लगाम लगाने के लिए थे। 39 आरोपी अहमदाबाद जेल में, 10 भोपाल जेल में, पांच बेंगलुरु जेल में, चार मुंबई की तलोजा जेल में और दो–दो दिल्ली, केरल के वियूर, जयपुर और बिहार की जेलों में बंद हैं। नावेद कादरी, जिसे बरी कर दिया गया है, केवल एक ही आरोपी था, जो 2018 से विस्तारित अस्थायी जमानत पर था, जब उसे सिजोफ्रेनिया का पता चला था। आईएम के कथित सह-संस्थापक यासीन भटकल सहित बाद में गिरफ्तार किए गए। हैदराबाद की एक अदालत ने 2016 में भटकल और चार अन्य को 2013 में शहर में हुए दोहरे विस्फोटों के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। वही अयाज सैयद, जो अब लगभग 38 वर्ष का है, जो अहमदाबाद के वटवा का निवासी है, पर अहमदाबाद शहर के नरोदा में साइकिल और एएमटीएस बस में बम लगाने का उसपर

आरोप था, जो सरखेज के पास फट गया। वह सरकारी गवाह बन गया और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सैयद को जून 2020 में गुजरात उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। उन्होंने मार्च 2019 में निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें क्षमा करने की मांग की गई थी। वही निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत आवेदन स्वीकार कर लिया था। वही फरवरी 2013 में, सीरियल ब्लास्ट के 14 आरोपियों पर 213 फुट लंबी सुरंग खोदने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जबकि वे साबरमती सेंट्रल जेल में बंद थे। अहमदाबाद शहर के रानिप पुलिस स्टेशन में एक नया मामला दर्ज किया गया और एक विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को 10 दिनों के लिए पूछताछ के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में दे दिया। पांच आरोपी–शाकिब निषार मोहम्मद इस्माइल उर्फ फुरकान मोहम्मद इरशाद, जाहिद उर्फ जावेद कुतुबुद्दीन उर्फ माजी शेख, नदीम अब्दुलनैम सैय्यद, इकबाल उर्फ इकसार कसांभाई शेख और उस्मान अगरबत्तीवाला गुजरात के हैं; केरल से तीन–तीन–सादुली अब्दुलकरीम, शिबली अब्दुलकरीम, और मोहम्मद अंसार उर्फ नदवी अब्दुलरज्जाक मुस्लिम और उत्तर प्रदेश से मुफ्ती

उर्फ अबुबशर अबुबक्कर शेख, सैफ उर रहमान उर्फ सैफू उर्फ सैफ अब्दुल रहमान, और इमरान इब्राहिम शेख और कर्नाटक से दो हाफिजुसैन ताजुद्दीन मुल्ला और नासिर अहमद लियाकतली पटेल है। दूसरी तरफ सरकारी वकील अमित पटेल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है और यह 2008 के सीरियल ब्लास्ट के फैसले से स्वतंत्र होगी। मामले के 14 आरोपियों में से 11 को दोषी ठहराया गया था; अन्य तीन-नासिर अहमद लियाकताली, साकिबनिसार शेख और नदीम अब्दुल नईम को बरी कर दिया गया है। बहरहाल, ध माकों के मुकदमे के लिए पहले नामित न्यायाधीश अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी हैं। बाद में कम से कम आठ न्यायाधीशों को मुकदमे की अध्यक्षता करने के लिए नामित किया गया, जिनमें बीजे ढांढा, वीपी पटेल, वीबी मयानी, ज्योत्सना याज्ञनिक, के.के. भट्ट, पी.बी. देसाई, पी.सी. रावल और ए.आर. पटेल शामिल थे। ज्ञात हो कि विशेष न्यायाधीश ए.आर. पटेल ने जून 2017 से मामले की अध्यक्षता की है।

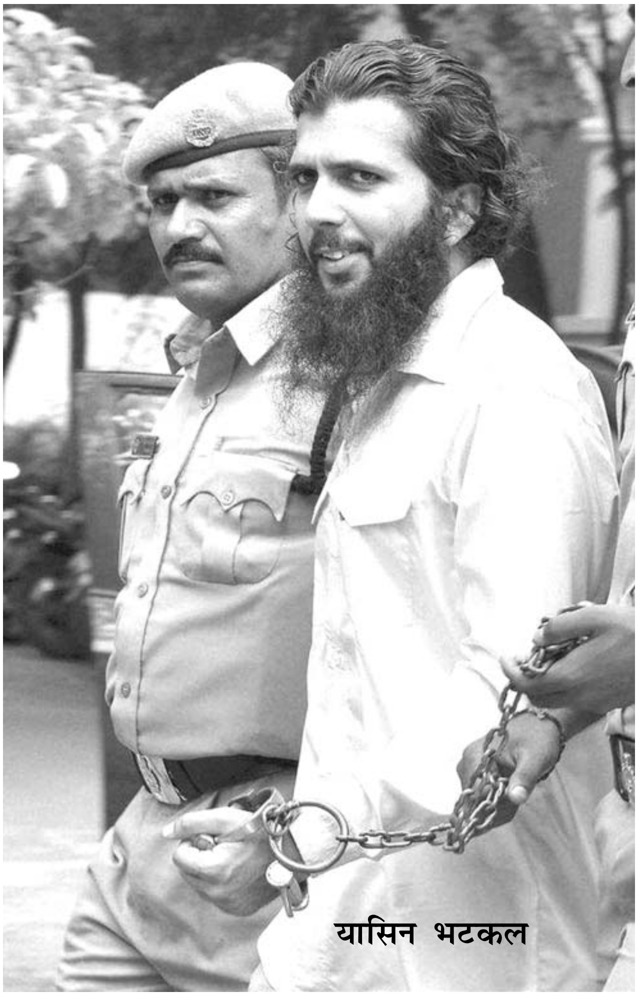

यासिन भटकल

सनद् रहे कि 2015 में, अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत से पहचान के लिए गवाहों को पंच करने के लिए आरोपियों की तस्वीरें दिखाने की अनुमति मांगी, क्योंकि वर्षों से आरोपी की उपस्थिति बदल गई थी। अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि इससे अभियोजन पक्ष को मदद मिल सकती है और कहा कि आरोपी की पहचान विवेक का नियम है, कानून का नियम नहीं है। वही सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली क्योंकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। 2019 में, अहमदाबाद की विशेष अदालत ने भोपाल सेंट्रल जेल में बंद 10 आरोपियों के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया और निर्देश दिया कि उन्हें साबरमती सेंट्रल जेल में रखा जाये। मध्य प्रदेश ने आदेश को चुनौती दी और गुजरात हाईकोर्ट ने अपने पक्ष में फैसला सुनाया। दिगर बात है कि अक्टूबर 2020 में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बचाव पक्ष को द इंडियन एक्सप्रेस, अहमदाबाद मिरर, संदेश और दिव्या भास्कर सहित कुछ अखबारों के संपादकों, पत्रकारों और फोटोग्राफरों की जांच करने की अनुमति दी जाये। आरोपी के आवेदन के अनुसार, रिपोर्ताज ने मामले में विसंगतियों की ओर इशारा किया था। इस पर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कोई भी जानकारी पत्रकारों द्वारा प्रदान की जाती है, जो कहीं से और किसी तरह से जानकारी लाने का प्रबंधन करते हैं और संपादक प्रकाशित करते हैं। सच नहीं हो सकता...। पत्रकारों को पुलिस थाने से, जांच अधिकारी से या यहां तक कि मुखबिर से सूचना मिली हो और हो सकता है कि मीडिया में लीक हो गई हो। सबसे दिलचस्प बात है कि एक कैदी के शिक्षा के अधिकार को लागू करते हुए, सितंबर 2013 में अदालत ने अहमदाबाद सेंट्रल जेल को मोहम्मद सामी बागेवाड़ी से जब्त की गई वास्तुकला पर दो किताबें वापस देने का निर्देश दिया। कर्नाटक के बीजापुर के रहने वाले बागेवाड़ी कर्नाटक के बेलगाम में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी

डीजीपी आशीष भाटिया एवं अन्य जांच टीम

विश्वविद्यालय में वास्तुकला के छात्र थे। अपनी गिरफ्तारी के बाद, वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका और परास्नातक के लिए दो विषयों की परीक्षा पास करना चाहता था। इसलिए उनके पिता ने उन्हें मार्च 2012 में सात किताबें दी थीं। अब बागेवाड़ी को बरी कर दिया गया है। कई अन्य अभियुक्तों ने भी जेल में रहते हुए शिक्षा प्राप्त की, जिनमें सफदर नागोरी भी शामिल हैं, जिन्होंने गांधीवादी दर्शन का अध्ययन किया और दोषियों में शामिल हैं।

गौरतलब हो कि सफदर नागोरी उन 38 दोषियों में से एक है, जिन्हें गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में मौत की सजा सुनाई थी। नागोरी और अन्य आरोपियों पर आतंकवादी कृत्यों के जरिए 56 लोगों की हत्या करने का आरोप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद नागौरी को सजा मिलने के बाद भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए भारत का संविधान मायने नहीं रखता। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी 54 वर्षीय नागोरी प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़ा था और अहमदाबाद विस्फोटों का मुख्य साजिशकर्ता था। जेल अधिकारियों के मुताबिक अहमदाबाद की विशेष अदालत में हुई सुनवाई में नागोरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। भोपाल सेंट्रल जेल के अधीक्षक दिनेश नरगवे ने कहा कि मौत की सजा दिए जाने के तुरंत बाद, नागोरी ने कहा, संविधान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए कुरान के फैसले सबसे ऊपर हैं। सिमी के पूर्व महासचिव नागोरी पर अहमदाबाद विस्फोटों के लिए विस्फोटकों की व्यवस्था करने और सिमी की अन्य गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया गया था। सूत्रों के मुताबिक नागोरी करीब 100 आपराधिक मामलों में आरोपी है। उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला 1997 में उज्जैन के महाकाल थाने में दर्ज किया गया था। नागोरी को 26 मार्च 2008 को इंदौर के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। नागोरी के पिता मध्य प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा में सहायक उप निरीक्षक थे। दूसरी तरफ 38 दोषियों के साथ फांसी की सजा पाने वाला मोहम्मद शकील बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र के लोहरका का का निवासी है। उसका परिवार कई साल पहले लोहारका से दिल्ली जाकर बस गया था। शकील का नाम दिल्ली के बम धमाकों में भी सामने आया था। लोहारका में शकील का घर अब खंडहर बन चुका है। दीवारों का सीमेंट भी झड़ चुका है। आस-पास झाड़ियां उगी हुई हैं। ग्रामीण बताते हैं कि शकील कंचे और गिल्ली डंडा खेला करता था। देखने में एक सामान्य लड़का लगता था। बचपन में ही शकील बाहर रहने लगा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। गांव के एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि बम धमाकों में नाम सामने आने के बाद परिवार के सदस्य इस गांव को छोड़कर चले गए थे। उनके दिल्ली में रहने की जानकारी मिली थी। लोहारका के ग्रामीणों ने बताया कि शकील के पिता लोहार का काम करते थे। वह सात भाई थे। उसके परिवार से लंबे समय से उन लोगों का ताल्लुक नहीं है। अब परिवार कहां रहता है, क्या करता है, इस बारे में वह कुछ नहीं जानते। गांववालों का कहना है कि यह तो स्पष्ट नहीं है कि परिवार को गैंग में शामिल होने की जानकारी थी या नहीं? वही वर्ष 2007 में खाजपुर/लोहरका के जंगलों में क्रिकेट खेल रहे कुछ युवकों को एक बंद पोटली में कई हैंड ग्रेनेड बम मिले थे। बाद में इन बमों को पुलिस ले गई थी। आशंका थी कि शकील ने ही इन बमों को यहां लाकर छुपाया है।

गौरतलब हो कि 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया

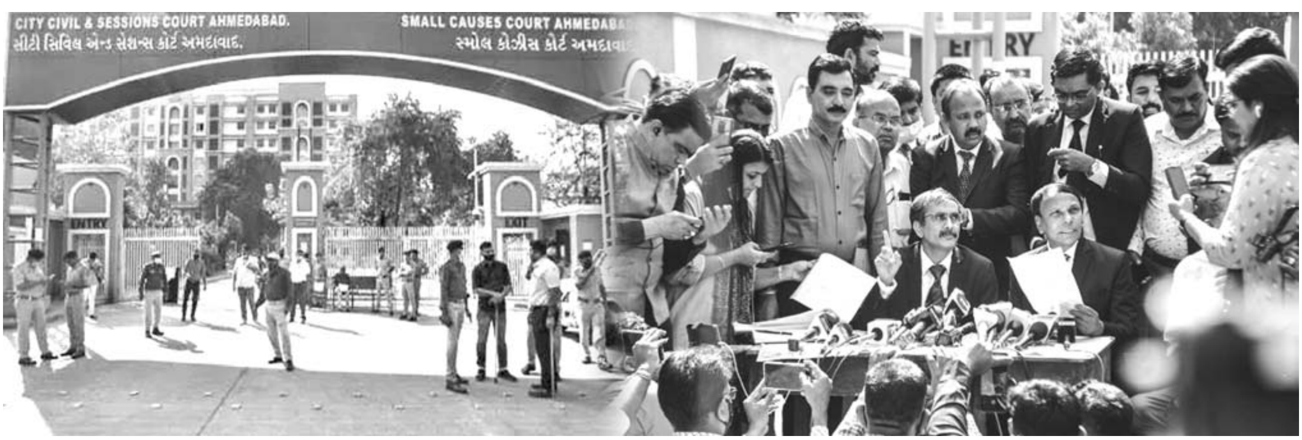

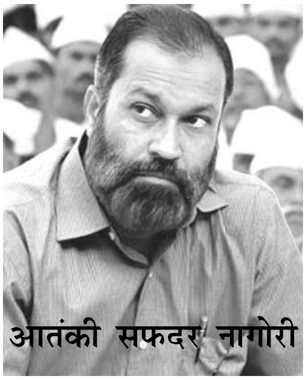
आतंकी सफ़दर नागोरी

था। 14 अलग-अलग जगहों पर 70 मिनट के अंदर 21 धमाकों में 56 बेगुनाह लोग मारे गए। धमाकों के दौरान डीसीपी अभय चुडास्मा गायकवाड़ हवेली के क्राइम ब्रांच ऑफिस में थे। नरोल के पास विस्फोट की सूचना मिलने के बाद डीसीपी ने मौके पर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ही उन्हें एक और विस्फोट की खबर मिली और 15 मिनट के अंतराल में यह पुष्टि हो गई कि शहर पर सिलसिलेवार धमाकों का हमला हो रहा है। टीमों को सौंपा गया था और बिना किसी और समय बर्बाद किए जांच की गई थी और शहर में बारिश हो रही थी। अचानक हुए ध माकों से नागरिकों में भारी अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया। क्राइम ब्रांच शक के दायरे में आए लोगों को हिरासत में ले रही थी। सभी मुखबिरों को अलर्ट कर दिया गया और शहर में ट्रैफिक जाम हो गया। करीब चंद मिनटों में पुलिस का वायरलेस नेटवर्क भी जाम हो गया। तभी एक मुखबिर ने फोन कर डीसीपी चुडास्मा को बताया कि आतंकी हमले में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, वह भरूच में थी। टीम भरूच पहुंची और वाहनों को जब्त कर लिया। उन्हें अपराधियों के संपर्क नंबर सफलतापूर्वक सौंपे गए जो जांच की मुख्य कुंजी बन गए। 26 जुलाई था जब अभय चुडास्मा और उनकी टीम ने उनके घर पर अंतिम भोजन किया। नवंबर माह तक पूरी टीम लगातार जांच पर काम करती रही। टीम में डीजीपी आशीष भाटिया, अभय चुडास्मा, राजेंद्र असारी, मयूर चावड़ा, वी.आर. तोलिया, उषा राडा, पीजी वाघेला, गिरीश सिंघल, हिमांशु शुक्ला, मयूर चावड़ा, के.के. पटेल और कई अन्य अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने दिन-रात जांच की।

बहरहाल, अहमदाबाद की एक अदालत ने 2008 के बम धमाकों के 38 आरोपियों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद एक बात का खुलासा हुआ कि वर्तमान के प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के षड्यंत्र रचा गया था। यह बात एक आरोपी ने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कबूली। आरोपी जानते थे तत्कालीन सीएम मोदी सिविल अस्पताल में घायलों की खबर लेने जाएंगे और इसीलिए वहां भी बम प्लांट किया गया था। इसके लिए पंचमहल में आरोपियों ने ट्रेनिंग भी ली थी। सरकारी वकील के मुताबिक आरोपी ने ये बात 2010 में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किये गए उसके बयान में कही थी जिसके बाद से इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने सीएम मोदी को सलाह भी दी थी के वो ऐसे वक्त में सिविल अस्पताल या अन्य जगह न जाएं मगर सीएम ने जान की परवाह किये बिना अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल पूछा और जांच एजनसीओ के साथ बैठक कर गुनहगारों की जड़ तक पहुंच उनके पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे।

हिजाब तो एक बहाना है! निशाने पर कुछ और है?

बेंगलुरु से मैसूर पहुंचने वाले राजमार्ग पर कर्नाटक की राजधानी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर स्थित मांड्या शहर के एक कॉलेज में बी. कॉम के दूसरे साल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा मुस्कान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने दूर इंग्लैंड में बैठे-बैठे ऐसा क्या देख लिया होगा कि वह उसके साथ खड़ी हो गई और भारत का यह छोटा-सा शहर दुनियां के नक्शे पर आ गया? मुस्कान ने 8 फरवरी को जो इतिहास बनाया, उसे भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आहटों के बीच अत्यंत पिछड़े समझे जाने वाले पच्चीस करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम समाज द्वारा ली जा रही करवटों से जोड़कर देखा जा सकता है। इन्हीं करवटों से पैदा होने वाला कंपन इस समय उत्तर प्रदेश के चुनावों में नजर आ रहा है जिससे लखनऊ और दिल्ली की सत्ताएं डरी हुई हैं।

मांड्या से सरकार को चुनौती इस बात की दी जा रही है कि वह तीन तलाक आदि को कुप्रथा बताकर मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने की बात तो करती है पर हिजाब को हथियार बनाकर बच्चियों को लिखने-पढ़ने से रोकना चाहती है। सरकार डरती है कि ये बच्चियां भी अगर पढ़-लिखकर नौकरियों में अपना हिस्सा और नागरिक अधिकारों की मांग करने लगेंगीं तो उसके उस बहुसंख्यक वोट बैंक में सेंध लग जाएगी, जिसके तुष्टिकरण के जरिए वह सत्ता की राजनीति करना चाहती है। 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर के मुताबिक, मुस्लिम बालिकाओं द्वारा स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश लेने की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। वर्ष 2007-2008 में देश की कुल मुस्लिम महिलाओं का केवल 6.7 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता था, पर 2017-18 में वह बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो गया। अपने गलों में भगवा शालें लपेटकर जय श्रीराम के नारे लगाते हुए छात्रों की भीड़ ने जब आठ फरवरी को मांड्या के कॉलेज में मुस्कान को घेर लिया तो उन्हें दूर-दूर तक अनुमान नहीं रहा होगा कि निरीह-सी नजर आने वाली लड़की आगे कुछ ऐसा भी कर सकती है जिससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी! उस नितांत अकेली छात्रा ने अपना दोपहिया वाहन पार्क किया और क्लास की तरफ बढ़ने लगी तभी उसकी नजर अपनी बाईं ओर गई। उसने गौर किया कि भगवा दुपट्टाधारी युवाओं का एक समूह उसकी तरफ देखते हुए 'जय श्रीराम' के नारे लगा रहा है। मुस्कान ने भी पलटकर जवाब दे दिया, 'अल्लाहुअकबर', 'हिजाब मेरा अधिकार है' और वह क्लास की ओर बढ़ती गई। युवाओं का झुंड भी चिल्लाता हुआ, उसका पीछा करता रहा। तभी पीछा कर रहे भगवा दुपट्टाधारी युवाओं से मुस्कान ने पीछे पलटकर सवाल किया कि उन लोगों को समस्या क्या है? वे लोग कौन होते हैं यह बताने वाले कि उसे अपना बुर्का उतार देना चाहिए! बाद में मुस्कान को कॉलेज के दो कर्मचारी अपने संरक्षण में इमारत में ले गए। सवाल अब बुर्के या हिजाब के पहनने या नहीं पहनने का ही नहीं बल्कि यह भी बन गया है कि क्या एक विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्ध उत्तेजक भीड़ ही यह तय करने वाली है कि किसे क्या पहनना या खाना होगा? उस स्थिति में देश के स्थापित संवैधानिक संस्थानों और अदालतों की भूमिका क्या रहने वाली है? मांड्या की घटना का दूसरा पहलू यह है कि 'जय श्रीराम' का उद्घोष करते युवाओं के उत्तेजक समूह से घिरी छात्रा 'अल्लाहुअकबर' के स्थान पर अगर 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' या 'भारत माता की जय' का नारा लगा देती तो फिर क्या होता? वे हिंदुत्ववादी तत्व, जो बुर्के को लेकर मुस्कान के पीछे पड़े थे, शायद बौखला जाते

मुस्कान खान

उन्हें सूझ ही नहीं पड़ती कि अब आगे क्या करना चाहिए! उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा जाए तो हिंदूवादी ताकतों द्वारा गोदी मीडिया की मदद से घटना को जिस तरह साम्प्रदायिक रंग में रंगा जा रहा है, वह प्रयोग असफल हो जाता। दूसरी ओर, वे तमाम कट्टरपंथी मुस्लिम महिला-पुरुष जो मुस्कान को अपनी आगे की लड़ाई का प्रतीक बनाकर शाहबानो के फैसले के समय के विरोध प्रदर्शनों को जगह-जगह पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनके पैर भी अपने घरों में ही ठिठक जाते, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी पीठ पीछे जय श्रीराम के नारों के साथ चीखते समूह से खौफ खाई हुई बालिका ने सुरक्षा कवच के रूप में उसका स्मरण कर लिया, जिसे वह अपना ईश्वर मानती है और दोनों ही तरफ की साम्प्रदायिक ताकतों को उनके मनमाफिक हथियार मिल गए। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी ट्वीट करने का मौका मिल गया कि मुस्कान को हिजाबी हुड़दंग का चेहरा बनाने वाले, हिंदुस्तानी मुस्कानों के(को!) तालीम, तरक्की की तालिबानी तबाही का मोहरा बनाते जा रहे हैं, खुदा खैर करे। नकवी से पूछा जा सकता है कि उन युवाओं को किस 'तालिबानी' तबाही का मोहरा बनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तानी मुस्कानों का भगवा

शाल-दुपट्टों और जय श्रीराम के नारों के साथ पीछा करते हैं और राष्ट्रीय तिरंगे को नीचे उतारकर भगवा झंडा आकाश में लहराने का दुस्साहस दिखाते हैं? कर्नाटक के एक मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि भविष्य में किसी दिन भगवा राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है और तब उसे लालकिले से भी फहराया जा सकेगा।

असली मुद्दा हिजाब, बुर्का या पर्दा नहीं बल्कि इन पहरावों को हथियार बनाकर देश में धार्मिक-साम्प्रदायिक ध्रूवीकरण और तनाव उत्पन्न करना है।जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब या बुर्का नहीं पहनतीं उनकी तरकध्कघी के लिए नकवी साहब के विभाग के पास कोई अलग से बजट नहीं होगा। यही स्थिति दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों और महिलाओं की पढ़ाई को लेकर भी है। सरकारों से उनके कामों को लेकर सवाल करने से रोकने का अधिनायकवादी तरीका यही है कि शोषित समाजों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए।शिक्षण संस्थाओं में सभी बच्चों को एक जैसी पोशाकों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के पीछे एक इरादा यह दिखाना भी हो सकता है कि सभी की पारिवारिक सम्पन्नता एक जैसी है और सभी के पेट समान रूप से भरे हुए हैं। अदालती फैसला अगर इसी बात पर होना है कि शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को ऐसे परिधानों में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं जिनसे उनकी धार्मिक पहचान उजागर होती है तो फिर उस फैसले में संविधान की शपथ लेकर उच्च पदों पर आसीन होने वाले व्यक्तियों के पहरावों और उनके सार्वजनिक आचरण को भी शामिल किया जाना चाहिए! मुस्लिम छात्राओं के मां-बाप भी पूछ रहे हैं कि जब हिंदू छात्राएं सिंदूर लगाती हैं, ईसाई छात्राएं क्रास पहनतीं हैं तो हमारी बच्चियों के हिजाब में क्या गलत है? इसका कौन जवाब देगा? मुख्तार अब्बास नकवी या अदालतें?

हमारे देश की महिलाएं

जहाँ अंतरिक्ष यात्रा कर ब्रह्माण्ड पर पहुँच चुकी है, वहाँ की महिलाओं के लिए धर्म जाति के अनुरूप पहनावे को लेकर राजनीति गलियारों में गहमागहमी का इस तरह बढ़ना सोच में डालता है कि क्या आज की स्थितियों में नारी-पुरुष समान है? क्या नारी, पुरुषों से किसी बात में कम है? देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार जीवनयापन की स्वतंत्रता है, वहाँ हिजाब की छाया डालकर नारियों को पीछे करने का यह मात्र एक राजनैतिक, धार्मिक षड्यंत्र नहीं है, तो क्या है? हमारे देश में कौम विशेष से संबंधित बुद्धिजीवी मानते हैं कि धार्मिक रूढ़ियों के कारण मुस्लिम महिलाओं की उतनी तरक्की नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए थी। धर्म की आड़ में आज भी नारियों को अनेक कुरीतियों से बाहर नहीं आने दिया जाता। मुस्लिम बहनों को उनके धर्म के अनुसार किशोरावस्था में आते ही हिजाब पहनने की हिदायतें शुरू हो जाती है, कारण बताया जाता है कि वे बाहरी पुरुषों की कुदृष्टि से हिजाब के जरिए बच सकती है तथा बाहरी व्यक्तियों से शर्म लिहाज रख सकती है। तो प्रश्न उठना जायज है कि क्या हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ कभी भी, कुछ भी बुरा नहीं होगा? क्या हिजाब पहनाने व पहनने वाले इसकी 100% ग्यारंटी दे सकते हैं? यहाँ कुदृष्टि तो पुरुष वर्ग की मानी जा रही है तो फिर हिजाब या पर्दा भी तो कुदृष्टि पर ही डाला जाना चाहिए।

बहरहाल हमारे यहाँ कानून में कुकृत्यों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। तो उनके होते अपनी बेटियों को हिजाब की दीवार में बंदी बनाकर रखना कौन सी समझदारी की बात है? धार्मिक अंधविश्वासों के चलते मुस्लिम बहनें जो किसी भी दृष्टि से पढ़ाई-लिखाई में कम नहीं होती उनकी समय से पहले शिक्षा बंद करवा दी जाती है। जिससे कई कार्पोरेट व ऊँचे-ऊँचे क्षेत्रों में वे पदों को सुशोभित नहीं कर पाती। आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम कोम में मात्र 3% महिलाएं ही सरकारी पदों पर कार्यरत् हैं। वे भी सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर ही। यह सब मुस्लिम महिलाओं की तरक्की में बाधक सिद्ध हो रहा है। कुरान तो सिर्फ शालीन कपडेघ् पहनने को कहता है ना कि हर महिला को पर्दे में रहने को। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षण संस्थानों में जब यूनिफार्म निर्धारित है जहाँ सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाने की व्यवस्था रहती है, वहाँ बुर्का

पहनकर अलग नजर आने की आवश्यकता ही नहीं। देखा जाता हैं कि बुर्का पहनने वाले संस्थानों में व अन्य जगह पर अलग नजर आते हैं और वे निर्धारित बुर्का आदि पहनने के कारण, अपनी जाति-समाज से अलावा अन्य किसी लोगों से मित्रता नहीं करते। जो उन्हें सामाजिक दायरे खुलकर जीने से रोकता है। जबकि हम अधिकाधिक लोगों से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तो नई बातें, ज्ञान व क्षमताओं से परिचित होते हैं। जो उन्नति के पथ पर बढ़ाने में सहायक होता है। आज भी हम देखते हैं कि हिंदू-मुस्लिमों में समानता भाव नहीं पनपा है। एक कारण और समझ से परे है कि हिजाब पहनने वाली बालिकाओं से पूछा जाता है, आप हिजाब क्यों पहनती हैं? तो वे कहती है कि - ष्हमारे धर्म के अनुसार यह जरूरी है और माता-पिता भी कहते हैं।ष बालिकाओं को पूछा जाता है बताइए क्या फायदा होगा? तो जवाब शून्य होता है। इन्हीं बातों के चलते उच्च तबके के मुस्लिम इन बंधनों में नहीं पड़ते। संस्कारों के नाम पर समानता में रोड़े सहीं नहीं है। आजाद भारत में हम अभी भी कुरीतियों से आगे नहीं बढेघ्गे तो कब नई राहों का अनुसरण करेंगे? हमें मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकारों पर बात करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। दरअसल, हिजाब या हिंदू महिलाओं के लिए पर्दाप्रथा उदारवादियों व रूढ़िवादियों के बीच चलने वाला एक ऐसा सांस्कृतिक द्वंद है, जिसमें समाज दो फड़ में बँट जाता है। हमें वास्तविक रूप से समानता, अधिकारों की रक्षा व सशक्तिकरण के लिए देखना चाहिए कि कुरान में भी पर्दे की व्याख्या ऐसी नहीं है कि उसे सब मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य माना जाए। कर्नाटक के उडुपी शहर से जन्मा हिजाब विवाद और फिर अभी तूल पकड़ता हिजाब गर्ल विवाद शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रथा बंद होने के साथ विराम पाना चाहिए। कई देशों में हिजाब गैरजरूरी हैं। यूरोप से लेकर श्रीलंका तक हिजाब प्रतिबंध कई बार लागू किया जा चुका है। तुर्की में भी ऐसे विवाद जन्में थे। मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की में यूरोप के समकक्ष समानता व आधुनिकता लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। विदेशों में कई बार सुरक्षा की दृष्टि से हिजाब को गैरकानूनी भी माना गया है। श्रीलंका में विगत दो वर्ष पूर्व इसका उदाहरण बना है। स्विट्जरलैण्ड में भी हिजाब प्रतिबंधित है। विदेशों में रोक लगाने पर इतनी राजनीति नहीं गर्माती जितनी हमारे देश में। वहाँ ऐसे विचारों को समानता का अधिकार माना जाता है और जनता सहर्षता से अपनाती है। हम अपने देश में शिक्षण संस्थानों में समानता लाने के लिए सभी जाति वाले एक जैसी यूनीफार्म पहने तो यह भी गलत बात नहीं होगी बल्कि एक अच्छी पहल होगी बदलाव की दिशा में। हमें इस बात पर गर्व करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ नारियों की समानता ,अधिकारों को ध्यान में रखकर उनकी उच्च शिक्षा प्राप्ति में वे अलग-थलग ना पड़ जाए, इसलिए एक यूनिफार्म के चलते उन्हें हिजाब ना पहनने को कहा गया है। वैसे भी यूनिफार्म तो समानता की द्योतक है। हमें समझदार होने की आवश्यकता है ना कि इसे राजनैतिक, धार्मिक या दार्शनिक रंगों से रंगने की।

हिजाब एक पाबंदी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना केवल मुस्लिम समुदाय में बल्कि किसी भी धर्म को अपनी अलग पहचान दिखाकर देश में ऐसे मामलों को तुल नहीं देना चाहिए। शिक्षा देते समय एक किताब से समान ज्ञान दिया जाता है वैसे ही समान वस्त्रों को पहनने में भी आपत्ति जैसी कोई बातें नहीं होना चाहिए। हमें हमारे देश की हर नारी को समान अधिकारों को दिलवाना है। महिलाएं व किसी को भी, धर्म विशेष के नाम पाबंदी में रखना इंसानियत नहीं है। देखा जाता है शोषण उसी का होता है जो गलत को सहन करता है। आज मुस्लिम महिलाओं को अपने आपको कठपूतली बनने से रोकना होगा, कुरीतियों को रोकने में सहायक बनना होगा। अपने आपको राजनीति की आग में झुलसने से बचाना होगा। अपना व आने वाली पीढ़ीयों का भविष्य संवारने में पहल करनी होगी। और सभी बहनों के लिए इतना ही कहना है कि किसी को ना दबाइए, ना दबिए, गलत को, कभी सही मत कहिए, मूक नहीं, आवाज बुलंद कीजिए, पंख परवाज से आसमान छुइए।

POLICE HANDCUFFED WOMEN PROTESTING SAND MINING IN BIHAR'S GAYA

A viral video from Bihar's Gaya district showing men and women in handcuffs has sparked outrage. The incident took place in Ahatpur village of Belaganj police station in Gaya district when a clash took place between the villagers and the police who were assisting government officials who had come to demarcate a river for sand mining. The villagers protested against the move and said it could flood the village during the rainy season. The villagers said the contractors and the police personnel started using force to drive them away which ensued into a clash. Niranjan Kumar and Pramod Yadav, residents of the village said, "The contractors appointed for sand extraction along with police came to demarcate the river. We reached peacefully to them in order to find a solution as the extraction will cause problems for the village during the rainy season and there can be a possibility of severe floods, but the police officers and contractors used force to drive us away." Police also fired tear gas shells, the villagers claimed. "Police fired tear gas shells at us. We ran to our houses, but they chased us to our houses and brutally thrashed us. Even the women, children and elderly people were not spared," the villagers added. They said that after thrashing them, many villagers including women were held captive with their hands cuffed and many among them were detained.SP Rakesh Kumar said some villagers "attacked" the police party following which nine policemen were injured. He also said that villagers also attacked the magistrate on whose instance a police case was filed.

Lalu Yadav granted bail by Jharkhand HC, hurdles cleared for coming out of jail

In a major reprieve the Jharkhand High Court on Saturday granted bail to former Bihar Chief Minister and RJD supremo Lalu Prasad Yadav in Dumka Treasury Case of the Fodder Scam which will now enable him to come out of jail. The court of Justice Apresh Kumar Singh granted the bail to Lalu Yadav. The court has instructed Lalu Yadav to furnish a bail bond of Rs 1 lakh and pay a fine of Rs 10 lakh. The court has said that as long as Lalu Yadav is out on bail, he can not leave the country without the prior permission of the court. Further, he should also not change his mobile number or address. Lalu Yadav had earlier got bails in two cases of fodder scam related to Chaibasa Treasury and another one related to Deoghar Treasury. Hearing is still on in the Doranda Treasury Case of the fodder scam. Lalu Yadav is currently admitted in AIIMS New Delhi where he is undergoing treatment for various health related ailments.He was airlifted from Ranchi to New Delhi on January 23, 2021.

JD(U) MP Baidyanath Prasad Mahto Dies After Prolonged Illnesses

JD(U) Lok Sabha MP from Valmiki Nagar and former Bihar minister Baidyanath Prasad Mahto died on Friday evening while undergoing treatment at the AIIMS in Delhi. He was 72. Mahto was on ventilator for a week. With the demise Mahto, total number of JD(U) member in the Lok Sabha has reduced to 15 from 16. Condoling his death, Bihar Chief Minister Nitish Kumar on Friday said Mahto was very popular in his constituency. His death has caused an irreparable loss to the state's political circle and society as well. Mahto won the 2009 and 2019 Lok Sabha elections from Valmiki Nagar constitu-

ency. Mahto had won the Valmiki Nagar seat by 3,54,616 votes. He had received a total of 6,02,660 votes. Congress candidate Shashwat Kedar, who came second, received 2,48,044 votes. He was earlier elected three times to the Bihar Legislative Assembly from Nautan. He was also Minister of Rural Development Department between 2005 and 2008 in Bihar government.

क्या सियासत की नई इबारत ? लिखेंगे ये पांच राज्य !

● ऋतुपर्ण दवे

क्या पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव वाकई देश की राजनीति में नया प्रयोग का रास्ता बनने जा रहे हैं। यूं तो अब तक इस मिथक को तोड़ नहीं जा सका है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। काफी हद तक सही भी है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड में बंट जाने के बाद भी हैसियत में किसी प्रकार की कोई कमीं नहीं आई। लेकिन राजनीतिक दलों के बनते, बिगड़ते समीकरणों से नया कुछ होने के आसार से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी मतदान गुप्त होता है। नतीजों के पूर्व तक आंकलन महज कयासों पर ही लगाया जाता है। बस कुछ उसी आधार पर 10 मार्च का इंतजार पूरे देश को बेसब्री से है। यह तो सही है कि जीतेगा तो लोकतंत्र, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में ऊंट किस करवट बैठेगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले अकेले उत्तर प्रदेश की हैसियत 10 मार्च को किस मोड़ पर होगी, महज कयास ही हैं। जाहिर है, इस बार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालात काफी अलग हैं।

सीधी टक्कर सत्ताधारी भाजपा व सहयोगियों तथा सपा व सहयोगियों के बीच दिख रही है। बसपा और कांग्रेस मैदान में जरूर हैं, लेकिन रेस में दिखते नहीं। 2017 की तरह इस बार किसी लहर का कहर न होने से बाकी दलों ने आस लगा रखी है। हां, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी नतीजे 2017 से इतर होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत का अपना एक अलग मिजाज है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को स्थानीय उम्मीदों व जातीय आधार पर तय करते हैं। अगड़े-पिछड़े और दलित मतदाताओं की भूमिका की छाप सबसे ज्यादा

उत्तर प्रदेश में ही दिखती है। वोट कटवा, बी पार्टी, डमी कैण्डिडेट और धार्मिक मुद्दों पर जैसी संवेदनशीलता उत्तर प्रदेश में दिखा करती है, वैसी शायद किसी दूसरे राज्य में उतनी नहीं। इस कारण भी इस बार के चुनाव काफी अलग से दिखने लगे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अयोध्या विवाद निपटारे के बाद, तेजी से बन रहे राम मंदिर और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का वादा कि साल 2023 में गर्भ गृह में रामलला को विराजमान कर दिया जाएगा और अयोध्या आने वाले श्रद्धालु दर्शन उनके मंदिर में ही कर सकेंगे, चुनाव में असर डालेगा। हिजाब का मसला भी ऐन चुनावों के वक्त भले ही सोची समझी चाल या महज इत्तेफाक हो, लेकिन अलग ढंग से भुनाने की कोशिशें होंगी। भले ही उत्तर प्रदेश के पहले चरण और दूसरे के मतदान के बाद राजनीतिक दलों के दावे कुछ भी हों, लेकिन नतीजों का पिटारा खुलने

के बाद ही समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश ने इस बार देश की राजनीतिक धारा मे अपना कैसा दबदबा बनाया। उत्तराखण्ड की सभी 70 व गोवा की 40 सीटों के चुनाव भी 14 फरवरी को निपट जाएंगे। उत्तराखण्ड चुनाव से ठीक पहले यहां भी हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वादा कि भाजपा सरकार बनी तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनेगी, जिसके दायरे में विवाह, तलाक, जमीन जायदाद व उत्तराधिकार के मामले भी शामिल होंगे, बड़ा राजनीतिक पैंतरा माना जा रहा है। भाजपा ने उत्तराखण्ड में बड़े-बड़े प्रयोग करते हुए चार साल के कार्यकाल में तीन मुख्यमंत्रियों बदले। पुष्कर सिंह धामी उनमें सबसे नए हैं। यहां आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली और दिल्ली पैटर्न का प्रचार कर अपनी जड़ें जमाने तो कांग्रेस साख बचाने के लिए संघर्षशील दिखी। लेकिन सत्ता के संघर्ष को लेकर ज्यादा कुछ बदले ऐसा लगता नहीं। सुन्दर समुद्र तटों और एक अलग तरह के खुलेपन के लिए मशहूर गोवा में भाजपा के लिए चुनौती पेश करने की कोशिशें कितनी सफल या विफल होती हैं यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन हां इतना जरूर है कि मनोहर पर्रिकर जैसे ईमानदार नेता की कमी जरूर गोवावासियों को खलती रही। पहली बार टीएमसी की धमाकेदार एंट्री से राजनीतिक समीकरण शुरू में जरूर बदलते दिखे। लेकिन कुछ ही दिनों में कइयों की रुखसती से बड़े करिश्मे की उम्मीद बेकार है। आम आदमी पार्टी भी यहां पूरी दमखम से चुनावी मैदान में दिखी जिसका फायदा तय है। लेकिन शिवसेना की गोवा में एँट्री और 10 सीटों पर उम्मीदवारी से सत्ता तक पहुंचने वालों को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, यह वक्त बताएगा। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद पणजी सीट से अपना उम्मीदवार वापस कर भविष्य के बड़े संकेत जरूर दे दिए हैं। कांग्रेस कहां होगी? क्या इस बार सत्ता तक पहुंच पाएगी, इस पर संदेह सभी को है। हां, आत्मविश्वास से लबरेज अरविंद केजरीवाल यहां भी दिल्ली सरकार का उदाहरण और सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी से भ्रष्टाचार के पूरी तरह खात्मे का भरोसा दिलाकर 24 घंटे फ्री बिजली देने का चुनावी वायदा कितना दमदार रहा, यह मतपेटियों के खुलने के बाद समझ आएगा। इस चुनाव में पंजाब की राजनीति एक त्रिकोण में जरूर फंसी दिखी। कैप्टेन अमरिंदर की कांग्रेस से विदाई और भाजपा से दोस्ती तो सिद्धू के अलग-अलग तेवरों बीच ऐन चुनाव से ठीक पहले दलित कार्ड खेलकर नए मुख्यमंत्री चन्नी को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करना पंजाब की राजनीतिक हवा का कितना रुख बदल पाएगा यह तो नहीं पता। वहीं आम आदमी पार्टी का भी भगवन्त मान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर मतदाता को लुभाना राजनीति में नया प्रयोग जरूर है। लेकिन लोकतंत्र से इतर है क्योंकि विधायकों के बने बिना ही हक छीनना बेजा लगता है। इसे तानाशाही कहें, थोपना या लोकतंत्र का चीरहरण थोड़ा मुश्किल है। यहां भी आम आदमी पार्टी को कमजोर आंकना बड़ी भूल होगी। भाजपा और अकाली दल आज भले ही एक-दूसरे के प्रतिद्विन्दी हों लेकिन दखल और धमक की अनदेखी करना बड़ी भूल होगी। पंजाब में सरकार किसी एक दल की होगी या फिर चुनावों के वक्त के कट्टर विरोध मिल- जुलकर सत्ता में बैठेंगे, देखने लायक होगा। लजीज पंजाबी डिशेज, मशहूर लस्सी के बीच ड्रग्स की सियासत से पंजाब की अलग बनती छवि का असर चुनावों पर असर डालता दिख रहा है। 20 फरवरी को पंजाब की नई राजनीतिक तकदीर मतपेटियों में होगी तब तक देखना है कि राजनीतिक शह और मात का खेल और क्या-क्या करतब दिखाता है। मणिपुर की 60 सीटों पर दो चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को चुनाव होंगे। मणिपुर हिन्दू बहुल राज्य है और आखिर में चुनाव है, सो देश के नामी गिरामी चेहरों की शिरकत होनी तय है। 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस यहां सत्ता से दूर रह गई। वहीं 21 सीटें जीत कर भाजपा ने स्थानीय दलों व विधायकों से

गठजोड़ कर सत्ता हासिल कर ली। इस बार भाजपा गठबंधन की खास सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की बगावत कितनी असरकारक होगी, यह नतीजे बताएंगे लेकिन भाजपा के 19 असंतुष्टों को टिकट देकर चुनाव को रोचक जरूर बना दिया है। जबकि कांग्रेस ने सेक्युलर दलों को साथ लेकर नई रणनीति बनाई है। बीते चुनाव में केवल 3 विधायक कम होने के बावजूद फौरन निर्णय में विफल कांग्रेस से 10 सीटें पीछे रहने वाली भाजपा सरकार बना ले गई। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो पाएगा या फिर कुछ नया होगा जो दिलचस्प होगा। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), नागा पीपुल्स फ्रण्ट (एनपीएस) के साथ ही वामपंथी खेमा भी पूरी तरह लामबन्द है, जिससे चुनाव का एक अलग ही माजरा नजर आता है। हाँ इतना जरूर है कि यहां की राजनीतिक सोच अनप्रिडेक्टिबल यानी अप्रत्याशित होती है। क्या इस बार भी होगी?

गौरतलब हो कि मिथ्या इस बात को लेकर भी है कि मोदी हार गए यूपी तो फिर क्या-क्या मुमकिन है? 10 मार्च को प्राप्त होने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे अगर भाजपा और संघ की उम्मीदों के खिलाफ चले जाते हैं, जैसी कि हाल-फिलहाल आशंका जाहिर की जा रही है और जीत 'कमंडल' के बजाय 'मंडल' की हो जाती है तो उस स्थिति में क्या भारत को एक हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की दिशा में संघ-भाजपा का हिन्दुत्व का कार्ड निष्प्रभावी साबित हो गया मान लिया जाएगा? क्या तब हिन्दुत्व का पूरा एजेंडा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? या उसका ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ परीक्षण किया जाएगा, देश के कोने-कोने

को हरिद्वार जैसी धर्म संसदों से पाट दिया जाएगा?

चुनाव परिणामों को दलों की हार-जीत के गणित से इतर भाजपा और संघ के हिन्दू राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ जोड़कर देखने की शुरुआत इसलिए कर देना चाहिए कि जो कुछ भी 10 मार्च को 5 राज्यों में तय होगा, उसी के बीजों से 2024 के लोकसभा के चुनाव और उसके भी पहले अन्य 11 राज्यों की विधानसभाओं की फसलें भी काटी जाने वाली हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति जिस तरह की भड़काऊ और आक्रामक जुबान का इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेता कर रहे हैं, उससे यही संकेत निकलते हैं कि उत्तरप्रदेश में मतदान हकीकत में भारत को एक हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के भाजपा के अलिखित घोषणापत्र पर मतदाताओं की सहमति प्राप्त करने को लेकर हो रहा है और उसे ही 80 बनाम 20 (या अब 90-10) के बीच का चुनाव बताया गया है। इससे पहले कि चुनाव परिणामों के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसों पर पहरे बैठा दिए जाएं, विचार करने का मुद्दा यह है कि सरकार न बना पाने या बहुमत के नजदीक पहुंचकर ठिठक जाने की हालत में भाजपा सारा दोष हिन्दुत्व की अतिवादी राजनीति को

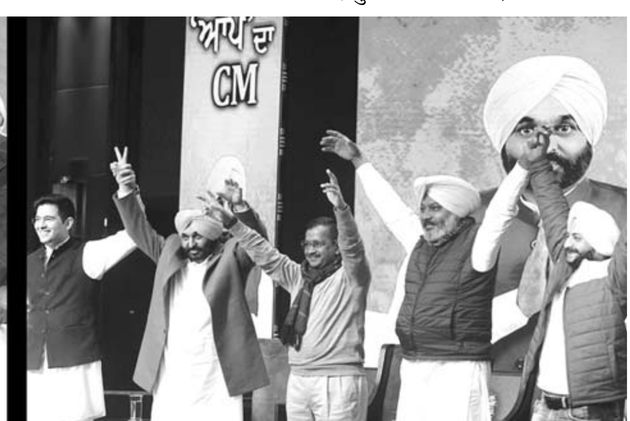

देते हुए अपने साम्प्रदायिक एजेंडे पर फिर से विचार करेगी या फिर पराजय का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी की प्रशासनिक खामियों और संगठनात्मक कमजोरियों के माथे पर फोड़ते हुए साम्प्रदायिक विभाजन के एजेंडे का और ज्यादा मजबूती और संकल्प के साथ विस्तार करना चाहेगी?

उत्तरप्रदेश के नतीजों की प्रतीक्षा एक अज्ञात भय के साथ इसलिए की जानी चाहिए कि भाजपा को मिलने वाली सीटों की संख्या और पड़ने वाले कुल मतों में उसका हिस्सा भारत को एक हिन्दू राष्ट्र में तब्दील करने की उसकी महत्वाकांक्षाओं के पक्ष या विपक्ष में जनता के समर्थन का प्रतिशत भी तय करने वाला है। इस तरह की आशंकाओं की प्रतिक्रिया ही मतों के विभाजन को रोकते हुए विपक्षी गठबंधन की सीटों में प्रकट होने वाली है। विपक्ष की मजबूत चुनौती के साथ-साथ केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के प्रति व्याप्त व्यापक नागरिक-असंतोष के बावजूद अगर भाजपा वापस सत्ता में आ जाती है तो उसे फिर योगी के कट्टर हिन्दुत्व का चमत्कार ही मान लिया जाएगा।

उत्तरप्रदेश के नतीजों को 'वहां सरकार कौन बनाएगा' से ज्यादा इन संदर्भों में भी देखने की जरूरत पड़ सकती है कि लोकसभा के लिए की जाने वाली तैयारी में भाजपा, संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों को अपने हिन्दुत्व की धार को और कितना तेज करने की जरूरत पड़ने वाली है और उसका नागरिक- राजनीतिक प्रतिरोध किस रूप में प्रकट हो सकता है? भाजपा की पराजय की प्रतिक्रिया में इस भय को भी शामिल किया जा सकता है कि अखिलेश के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को लोकसभा चुनावों तक बचने वाले 2 वर्षों के दौरान धार्मिक आतंकवाद की घटनाओं से मुक्त रहकर विकास के एजेंडे पर काम ही नहीं करने दिया जाए, पिछले 5 वर्षों के दौरान शासन-प्रशासन पर कब्जा कर चुके निहित स्वार्थों द्वारा उसके पैर जमने ही नहीं दिए जाएं और उसे उस तरह का साबित करने की हरेक दिन कोशिश की जाए, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री अपनी वर्चुअल सभाओं में कर रहे हैं?

मोदी मतदाताओं को लगातार आगाह कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी का मतलब दबंगों और दबंगई के

शासन को उत्तरप्रदेश में वापस लौटाना होगा। उत्तरप्रदेश में 2017 की तरह के बहुमत के साथ भाजपा का सरकार नहीं बन पाना न सिर्फ 2024 में प्रधानमंत्री की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को प्रभावित करेगा, मोदी की पार्टी और संघ पर पकड़ के साथ-साथ देश की जनता पर उनके तिलिस्म और उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि में भी दरारें पैदा कर देगा। चूंकि आंतरिक प्रजातंत्र के मामले में भाजपा की विश्वसनीयता कांग्रेस जितनी पारदर्शी कभी नहीं रही, इस बात का कभी ठीक से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकेगा कि मोदी को कमजोर होते देखने की कामना करने वाले नेता-कार्यकर्ताओं की भाजपा और संघ में तादाद कितनी बड़ी होगी? विधानसभा के विपरीत परिणामों की स्थिति में योगी आदित्यनाथ तो लखनऊ से गोरखपुर लौटकर फिर से अपने मठ के पूजा-पाठ में ध्यान लगा सकते हैं, पर 2024 में लोकसभा चुनावों के अनपेक्षित नतीजों की हालत में मोदी को लेकर ऐसी कल्पना कतई नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री कभी सत्ता से बाहर भी रह सकते हैं या विपक्ष में भी बैठने का उनमें कोई साहस है? मोदी ने वर्ष 2001 में गुजरात विधानसभा में पहली बार प्रवेश मुख्यमंत्री के तौर पर ही किया था और फिर गांधीनगर से सीधे संसद में भी प्रधानमंत्री के तौर पर ही दाखिल हुए थे। वर्ष 2024 तक मोदी सत्ता में बने रहने के 23 साल पूरे कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू कुल 16 साल 286 दिन और इंदिरा गांधी (2 चरणों में) 15 साल 350 दिन ही सत्ता में रह पाईं थीं। आपदाओं को आमंत्रित कर उन्हें अवसरों में बदल देने की महारथ रखने वाले मोदी के राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले शोधार्थी जानते हैं कि प्रत्येक विपरीत परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री के पास एक प्लान-बी का जादुई हथियार अवश्य मौजूद रहता है, जो पिछले लगभग 8 सालों में कई बार अवतार ग्रहण कर चुका है। अतः जो लोग इस समय योगी की नजरों से उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा के लिए संकट ढूंढ रहे हैं, वे 10 मार्च के बाद मोदी की नजरों से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किसी प्लान-बी की प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। मोदी अब न तो अपने लिए सत्ता को छोड़ सकते हैं और न ही संघ के लिए हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का एजेंडा। संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के जवाब में प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में जिस कटुता और विद्वेष की भावना के साथ विपक्ष पर आक्रमण किया, उसमें चुनाव परिणामों के बाद बनने वाली राजनीति के स्पष्ट संकेत ढूंढे जा सकते हैं? देश की जनता को बस अपनी तैयारी रखनी चाहिए।

बहरहाल, पांच राज्य मिलकर देश में 2024 में बनने वाली नई सरकार की तकदीर की तदबीर लिखेंगे या फिर अकेले उत्तर प्रदेश से ही यह रास्ता हमेशा की तरह निकलेगा? इंतजार है 10 मार्च का, नतीजे कुछ भी हों अगले आम चुनावों के लिए जहां ये लिटमस टेस्ट तो होंगे ही, वहीं मुमकिन है कि राजनीति की नई इबारत भी बनें।

India's PSLV-C52 successfully puts EOS4, 2 small satellites into orbit

The Indian Space and Research Organisation on Monday successfully launched the fourth Earth Observation Satellite (EOS-04) onboard the Polar Satellite Launch Vehicle. The PSLV-C52 blasted into space at 5.59 am from the first launchpad at the Satish Dhawan Space Centre, after a 25-hour countdown, putting the first mission launch of 2022 into action. The countdown process of 25 hours and 30 minutes leading to the launch commenced at 4.29 am on Sunday after authorisation by the Launch Authorization Board. Two other satellites shared rides along with the EOS-04 that was placed in the Sun-Synchronous Orbit nearly 529 km above the earth. The four-stage rocket lifted off with a student satellite INSPIRESat and a spacecraft dubbed INSAT-2DT -- a precursor of a joint Indo-Bhutan mission for future.

The Mission Control Room was abuzz, as the launch director announced that all three satellites were successfully deployed. ISRO chief S Somnath said: "The mission of PSLV-C52 has been successfully accomplished." The EOS-04 is also Radar Imaging Satellite (RISAT) and has been designed to provide high-quality images under all weather conditions to aid applications meant for agriculture, flood mapping, soil moisture, forestry, plantations and hydrology. The spacecraft will collect observation data in C-Band furthering the work done by Resourcesat, Cartosat, and RISAT-2B series. The satellite has an operating life of a decade. The 8.1-km INSPIRESat-1 has been developed by the Indian Institute of Space Science & Technology in association with the Laboratory of Atmospheric & Space Physics at the University of Colorado. The satellite with a one-year-lifespan will aim to improve our understanding of the dynamics of the ionosphere and the sun's coronal heating process.

This was the first launch of PSLV since the failure of the EOS-03 mission in 2021. ISRO had declared that mission a failure citing a technical anomaly with the system. With the first launch of 2022, ISRO has set in motion 18 other missions planned for later this year, including the high profile launch of Chandrayaan-3 to the Moon and the much-awaited unmanned Gaganyaan. This mission of PSLV saw the launcher climb up in the SSO. The space agency plans to conduct the PSLV-C53 mission in March, which will carry OCEANSAT-3 and INS 2B ANAND into orbit. Somnath earlier had said the agency plans five major satellite launches in the coming three months and a total of 19 missions this year.

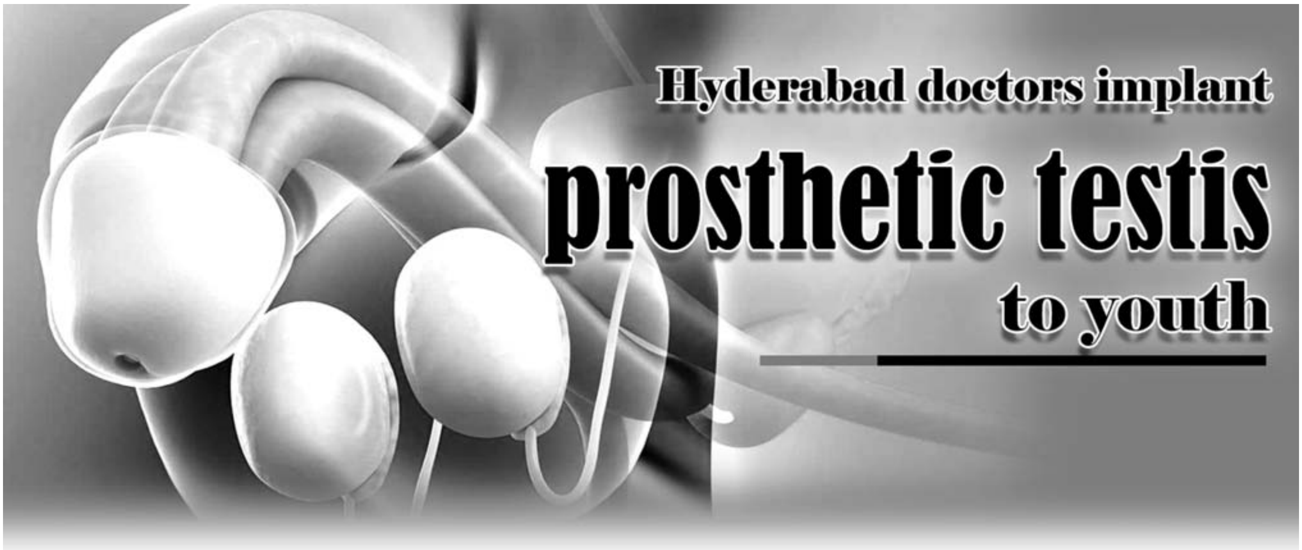

Hyderabad doctors implant prosthetic testis to youth

Doctors at KIMS hospital in the city have implanted prosthetic testis to a youth after his left testis came to a dead state, due to genetic reasons in his younger days. This prosthetic testis, which is made of silicon, gave the patient a lot of relief psychologically, the hospital said in a release here on Sunday. KIMS Hospital Urologist Consultant Dr Navuluru Upendra Kumar, while explaining the case details and the surgical procedure they performed said, "an 18-year-old boy had recently approached the hospital with severe pain in his left testicles some four years ago. On testing, we came to know that the left testis was twisted and due to loss of blood supply, it came to a dead state, he said as the dead testis pose danger to the right one, we have removed the dead left testis and advised the young boy to come for the follow-up after a year." "But the youth couldn't come again due to the COVID pandemic and now, he is fully grown up and is at the age of 23, worrying about his marital life," Dr Kumar said.

"The youth came to KIMS hospital once again recently and we have decided to implant a prosthetic testis, made of silicon, the Urologist said. One in a thousand will have such a problem, where their testis may get damaged. Testis gets twisted due to genetic reasons. In such cases, the blood supply to the testis will stop, and they will get severe pain," the doctor said. "He said they usually give some antibiotics for a week to treat the swelling but it will give temporary relief and the problem will reoccur. If the patient visits any urologist within 4 to 6 hours of getting pain, they can restore the blood supply and save the testis. If they come late, there is no other way than removing the dead testis, he stated. In this case, the Youth also approached the hospital late and after the implant a prosthetic testis, the youth will not have any problems with his marital life in future as his second testis is safe." "He will have a normal family life and fertility too. The silicone material will not cause any kind of infection. They are available for a long period, but most of the doctors are not using this. Patients will get a lot of relief," Dr Upendra Kumar added.

मोहन भागवत द्वारा धर्म संसद का विरोध अतिवादी और विरोधी

● अवधेश कुमार

मोहन भागवत द्वारा हाल में हिंदुत्व को लेकर अतिवादी आक्रामक बयानों की आलोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि इससे उस पूरे समूह में नाराजगी है, जो हिंदुत्व के नाम पर अतिवादी विचारों व व्यवहारों के समर्थक हैं। भागवत का यह कहना उन सबको नागवार गुजर रहा है कि धर्म संसद में जो कुछ कहा गया वह हिंदुत्व बिल्कुल नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व से संबंधित नागपुर के कार्यक्रम में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और अन्य प्रश्नों पर विस्तार से बोला है और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की अधिकृत सोच मानी जाएगी। भागवत ने जो कुछ कहा वह नया नहीं है। दुर्भाग्य से सही समझ, सोच, नेतृत्व और मार्गनिर्देश के अभाव में पिछले कुछ वर्षों में हिंदुत्व की प्रतिक्रियावादी व्याख्या और उसके अनुसार व्यवहार करने वालों का समूह विकसित हुआ है। समस्या यह है कि हमारे देश में जब भी हिंदुत्व के नाम पर प्रतिक्रियावादी समूह या तत्व कुछ बोलते या कदम उठाते हैं तो उसे सीधे-सीधे संघ, भाजपा या पूरे परिवार से जोड़ दिया जाता है। दूरगामी व्यापक लक्ष्यों के साथ अग्रसर कोई संगठन समूह इस तरह के अतिवादी विचार से स्वयं को कभी बांध नहीं सकता। विश्व इतिहास गवाह है कि प्रतिक्रियावादी विचारधारा वाले संगठन या समूहों की आयु बहुत लंबी नहीं होती। ऐसे लोगों को माहौल के कारण आरंभ में कुछ दिनों तक कुछ लोगों का समर्थन अवश्य मिलता है पर ये स्वयं अपने जीवन काल में ही कमजोर या अलग-थलग पड़ जाते हैं। अतिवादी घटनाओं की प्रतिक्रियाओं को तात्कालिक जन समर्थन मिलनि स्वाभाविक होता है। किंतु सतत रूप से प्रतिक्रियावादी बने रहना किसी को भी उस विचारधारा की सच्ची और गहरी समझ से दूर रखता है। इस कारण उनके विचार और व्यवहार दोनों कभी भी संतुलित सहज स्वाभाविक और स्वीकार्य नहीं होते। हालांकि यह दुर्भाग्य एकतरफा नहीं है। हिंदुत्व शब्द का विरोध करने वालों के साथ भी यही समस्या है। वे कतिपय नकारात्मक कारणों से जानबूझकर या अज्ञानता में हिंदुत्व की गहराई और व्यापकता को समझे बिना ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। सीध े-सीधे हिंदू धर्म के अलावा अन्य सभी मजहबों और संप्रदायों के विरुद्ध घृणा व नफरत पैदा करने वाली विचारधारा के रूप में हिंदुत्व को व्याख्यायित किया जा रहा है। तस्वीर ऐसी बनाई जाती है मानो हिंदू धर्म की व्यापकता से परे निहायत ही संकुचित फासीवादी आक्रामक या उग्रवादी हिंसक तत्वों ने इस विचारधारा को अलग से जन्म दिया है। ये भी अपने विरोध और निंदा में सीमाओं का अतिक्रमण कर नकारात्मक अतिवाद का शिकार हैं। जैसे हिंदुत्व के नाम पर प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों या समूह की व्याख्या गलत है वैसी ही इनकी भी। वे कहते हैं कि हमें इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो वाकई कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ यहां केवल एक ही धर्म रहेगा। दूसरी तरफ हिंदुत्व के विरोध में झंडा उठाने वाले भी यही दुष्प्रचार करते हैं कि संविधान से सेकुलर शब्द हटाकर हिंदू राष्ट्र लिख दिया जाएगा और लाल किले पर तिरंगा की जगह भगवा फहराया जाएगा। इनकी प्रतिक्रिया में वे कहते हैं कि हां ऐसा ही होना चाहिए। धर्म संसदों में दिए गए कई भाषणों में आपको इससे भी आगे की भाषा सुनाई देगी। दुर्भाग्य से हिंदुत्व से अनभिज्ञ या जानबूझकर इसके विरोध करने वालों को निंदा और दुष्प्रचार का पूरा आधार मिल जाता है। भागवत का पूरा वक्तव्य इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए दिया गया लगता है। संघ परिवार की विचारधारा को निष्पक्ष होकर पढ़ने और समझने वाले मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र से उनका अर्थ न संविधान बदलना है और न ही लाल किले या अन्य सरकारी संस्थानों पर तिरंगा हटाकर सीधे भगवा ध्वज फहरा देना है। भागवत ने कहा भी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र है ही। मूल समस्या हिंदू और राष्ट्र शब्द को न समझ पाने के कारण पैदा होती है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्र का अर्थ वह नहीं है जो हम नेशनल स्टेट का मानते हैं। राष्ट्र का अभिप्राय ऐसी जीवन प्रणाली से है जो उस क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनाया हुआ है। इस दृष्टि से देखें तो भारत की संपूर्ण जीवन प्रणाली में हिंदुत्व स्वयमेव समाहित है। भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं कहने का तात्पर्य मजहब बदलकर सबको हिंदू धर्म में लाना नहीं हो सकता। राष्ट्रीयता के रूप में सभी हिंदू हैं उनका मजहब कोई भी हो सकता है। यह विचार केवल एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या वीर सावरकर जैसे लोगों का नहीं है। आप विवेकानंद से लेकर महर्षि अरविंद जैसे मनीषियों के विचारों को पढ़ेंगे तो उसमें भी यही भाव साफ-साफ परिलक्षित होता है। इस श्रेणी के सारे मनीषी अपने भाषणों में हिंदू राष्ट्र शब्द का सहजता से प्रयोग करते हैं क्योंकि तब इसके बारे में इतनी भ्रांत धारणाएं नहीं बनाई गई थी और न इसका इस तरह विरोध था। महर्षि अरविंद ने 1893 के अपने उत्तरपारा भाषण में ही हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी विवेकानंद भारत के संदर्भ में समानार्थी के रूप में हिंदू राष्ट्र का प्रयोग करते हैं। वे सब इसलिए ऐसा करते थे कि उन्हें अपनी धर्म संस्कृति के साथ राष्ट्र के वास्तविक अभिप्राय का बोध था। यह बात सही है कि विश्व भर

में इस्लामी अतिवाद के डरावने उभार तथा भारत में उसके असर के कारण हिंदू समाज के अंदर व्यापक प्रतिक्रियाएं हुई। सरकारों द्वारा सच्चाई न स्वीकार करने के कारण लोगों के अंदर गुस्सा भी पैदा हुआ और उसका प्रकटीकरण लोगों ने अन्य पार्टियों के विरुद्ध भाजपा को समर्थन देने के रूप में किया। लेकिन इसके समानांतर ऐसे तत्व भी विकसित हो गए जिनके लिए हिंदुत्व का अर्थ अन्य सभी मजहब का नकार तथा उनके मानने वालों से नफरत है। वे नाथूराम गोड्से जैसे एक हत्यारे को भी राष्ट्रभक्त कह कर उनका समर्थन करते हैं। हिंदुत्व की सर्व कल्याणकारी और व्यापक अवधारणा में दूसरे मजहब से नफरत और इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान ही नहीं है। किसी मजहब के विचारों से असहमति या उसकी आलोचना करने में समस्या नहीं है किंतु ठोस तथ्यों पर आधारित होने के साथ उसकी भाषा अनुशासित और मर्यादित होनी चाहिए। इसी तरह किसी मजहब के अतिवादियों का विरोध करना भी उचित है किंतु उसमें उसी तरह के आचरण की आक्रामक वकालत हिंदुत्व के व्यापक लक्षणों के विरुद्ध है। वैसे भी हिंदुत्व और हिंदुत्व विरोधियों के बीच संघर्ष विचारधारा का है। इनका उत्तर विचारधारा और उसके आधार पर विकसित जन समर्थन से ही किया जाना चाहिए। भागवत ने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिंदुत्व के सभी पहलुओं की एक बार फिर से व्याख्या कर हिंदुत्व और हिंदुत्व मवादियों के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा पैदा किए जा रहे भ्रमों का खंडन करने की सुविचारित प्रभावी कोशिश की है। उम्मीद करनी चाहिए कि इसका असर होगा और भ्रम के शिकार लोग भी अपनी सोच व व्यवहार पर पुनर्विचार करेंगे। राजनीतिक या अन्य कारणों से हिंदुत्व विचारधारा के विरोध करने वालों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन अगर स्वयं को हिंदुत्ववादी कहने वालों ने अपने व्यवहार को इसकी व्यापकता के अनुरूप संशोधित परिवर्तित नहीं किया तथा यह गलतफहमी पाले रहे कि संघ और भाजपा इसी विचारधारा को मानती है तो वे अपने साथ हिंदुत्व विचारधारा को ज्यादा क्षति पहुंचाते रहेंगे।

वीर सावरकर : हिन्दुस्तान के वो सबसे विवादित क्रांतिकारी, जो कवि भी थे

● **नवीन रांगियाल**

एक क्रांतिकारी होने से परे विनायक दामोदर सावरकर का एक साहित्यिक चरित्र भी रहा है। भले ही गांधी हत्या के कलंक के चलते उनका यह पक्ष बेहद साफतौर पर उजागर नहीं हो सका राजनीति में जब भी हिंदूत्व और दक्षिणपंथ को लेकर कोई बहस छिड़ी, तब-तब विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी अंडरलाइन किया गया। 'गाय पर राजनीति' हो या 'गांधी हत्या' को लेकर कोई तर्क। ये सारी बहसें सावरकर के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती है। धुंधले तौर पर ही सही लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में सावरकर आज भी जिंदा हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी होने के अलावा विनायक दामोदर सावरकर का एक साहित्यिक चरित्र भी रहा है या कहें एक साहित्यिक एंगल। भले ही गांधी हत्या के कलंक के चलते उनका यह पक्ष बेहद साफतौर पर उजागर नहीं हो सका, या नजर नहीं आता या उसके बारे में बहस नहीं की जाती हो, लेकिन उनका एक लेखकीय पक्ष भी रहा है, जिससे उनका एक संवेदनशील चरित्र सामने आता है। सावरकर क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन वे कवि थे, साहित्यकार और लेखक भी थे। हो सकता है, क्रांतिकारी मकसद की वजह से उन्होंने अपने इस हिस्से को हाशिए पर ही रख छोड़ा हो। लेकिन वे शुरू से पढ़ाकू और लिक्खाड़ किस्म के व्यक्ति रहे हैं। उनका लेखन बचचन से ही शुरू हो जाता है। उन्होंने बचपन में कई कविताएं लिखी थीं। बड़े होने पर भी उन्होंने अपनी यह प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। साल 1948 में गांधी की हत्या के कुछ ही दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि अगले ही साल सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया जाता है। अंडमान निकोबार में 'काला पानी' की सजा के दौरान करीब 25 सालों तक वे किसी न किसी तरह से अंग्रेजों की कैद में रहते हैं, लेकिन इस कैद और निगरानी के बीच भी उनका लेखन कर्म जारी रहता है। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी 'हिंदुत्व-हू इज हिंदू?' जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। सावरकर के बेहद ही समर्पित लेखक होने के प्रमाण तब सामने आए जब वे अंडमान निकोबार की जेल से 'काला पानी' की सजा से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आते ही वे सबसे पहले वो काम करते हैं,जो उन्होंने जेल में किया था। उन कविताओं को लिखने का काम करते हैं जो अब तक उन्होंने जेल की दीवारों पर लिखीं थीं। दरअसल, अपनी सजा के दौरान सावरकर ने अंडमान निकोबार की जेल की दीवारों पर करीब 6 हजार कविताएं दर्ज कीं थीं। चूंकि उनके पास लिखने के लिए कोई उस समय कलम या कागज नहीं था, इसलिए उन्होंने नुकीले पत्थ्थरों और कोयले को अपनी कलम बनाकर दीवारों पर लगातार कविताएं लिखीं। इसके बाद वे कविताएं दीवारों पर ही खत्म्म न हो जाए, इसलिए उन्हें रट-रट कर कंठस्थ्थ किया। जब जेल से बाहर आए तो उन्हें कागज पर उतारा।इतना ही नहीं, उनकी लिखी 5 किताबें उनके नाम से प्रकाशित हैं। सावरकर द्वारा लिखित किताब 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस' एक ऐसी सनसनीखेज ब्यौरा थी, जिसने अंग्रेज शासन को लगभग हिलाकर रख दिया था। उनकी कुछ किताबों को तो दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था।

The online gaming revolution that is helping India showcase its tech talent

The worldwide boom of online gaming is allowing India to export its growing industry of game development to international levels. Game development studios like Moonfrog Labs or Gameberry Labs have produced world- recognized games that have topped and even continue topping download ranks in app stores. In effect, society has shifted a long time ago to digital platforms to look for ways to satisfy their entertainment needs, and in this regard, the gaming industry has benefited from the digital revolution. From the shooter frenzy of online games like Counter-Strike to free-to-play games like League of Legends and Fortnite, it seems as if the digital realm is the ideal place to develop and spread the popularity of games.

Even classic games are finding their way to digital platforms. Board Game Arena is an online platform that accounts for more than 7 million active users on its website. They offer digitalized versions of traditional board games available to play online and between players all around the world. Another very popular category in the gaming landscape is the online casino industry. Just as with traditional games, online casino platforms have managed to adapt to the digital world by recreating classic land-based casino games in their online versions. Games like poker, blackjack, roulette, or slots are just some of the most popular among gamers. The best providers of online casino games offer their clients attractive bonuses to try a variety of games or to reward their activity. Precisely in the category of classic games, an Indian game development studio like Gameberry Labs managed to launch in 2017 the award-winning online game Ludo Star, better known in India as Parchisi, a classic board game widely popular in Spain and Latin America. Played by 6 million users across 15 countries, the game experienced a rapid rise in 2019 and 2020 due to the pandemic and people staying in homes needing ways to keep sharing with loved ones at distance.

Ludo Star was initially a success in Pakistan where it rapidly became the number 1 downloaded app for months, even making the news for its success among gamers. So rooted it was in the gaming culture of Pakistan, that it became very popular in Saudi Arabia at the same time, as Pakistani immigrants quickly received the news of the game of their families and friends. Then came Parchisi Star, a slightly different version of Ludo Star targeted for the Spanish culture that has been very successful as well. And from there, the list continues to grow with more games like Bankrupt, another board game, Word Pirate Adventure, a word learning game,and Woodblock Puzzle, a classic puzzle game. Gameberry labs is based in Bengaluru which is a region known as a specialized hub in the tech industry. It has been baptized as the Silicon Valley of India as it historically concentrates the best IT talent in India. But the rapid growth of the sector has made it that other cities like Mumbai host Indian studios like GameNagri or JetSynthesys that recently partnered with Square Enix, one of the biggest game developers in the world. The Japanese studio is known for its famous RPG, Final Fantasy, one of the biggest franchises in videogame history. Square Enix chose India's JetSynthesys to launch Ludo Zenith, another game inspired by the success of Ludo Star. Now the next frontier to explore for the online gaming community in India will be the one opened by the rapid rise of NFT's and blockchain technology. The revolution of play-to-earn games will be the next phenomenon in online gaming as players get financially rewarded for spending their time playing games.

The most popular play-to-earn NFT game of 2021 was Axie Infinity, a game inspired by the famous franchise of Pokémon, where players get to form a team of creatures called Axies that are used to battle opponents and to complete daily tasks required to win prizes and tokens that serve as the own cryptocurrency of the game, and therefore, the possibility of making money through the game. If Indian studios can replicate their success with mobile gaming with the new wave of NFT gaming, then it could settle India as one of the leaders in the online gaming industry.

मोदी के नक्शेकदम पर शिवराज

● **अरविन्द तिवारी**

भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विथ डिफरेंस और काडर बेस पार्टी कहा जाता है। बात करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की, तो वे जहां भी जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं। पिछले दिनों वो दक्षिण भारत के एक प्रांत में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। तब उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसमें वो परंपरागत परिधान धारण किए हुए दिखाई दिए। वैसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी पीएम मोदी को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते है या यूं कहें कि वे पीएम की राह पर चल रहे हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने भी वही लिबास धारण किया, जो पीएम ने किया था। अलबत्ता जब सीएम शिवराज दर्शन के लिए पहुंचे, उस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां थे। यह महज संयोग ही था। लेकिन विरोधी पार्टी ने तो कटाक्ष करना भी शुरू कर दिए हैं और सीएम शिवराज को भविष्य के पीएम शिवराज बताने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। ग्वालियर में तैनात अफसरों चाहे वह कमिश्नर हो या आईजी या कलेक्टर हो और एसपी को इन दिनों अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाने से ज्यादा मशक्कत दो दिक्कत केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को साधने में करना पड़ रही है।

दरअसल, ग्वालियर से जुड़े मामलों में ये दोनों दिग्गज नेता चाहते हैं कि सब कुछ उनके मुताबिक हो। हालत यह है कि यदि तोमर की पसंद पर कोई काम हो जाता है तो सिंधिया समर्थक उसे पचा नहीं पाते हैं और अपने आका से कहकर उसमें बदलाव करवा देते हैं। यदि सिंधिया की पसंद पर कोई फैसला होता है तो तोमर समर्थक अपने तेवर दिखाने से पीछे नहीं रहते हैं और जैसा वे चाहते हैं, वैसा करवाने के लिए अफसरों के पीछे पड़ जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में 1 दर्जन से

शिवराज सिंह चौहान

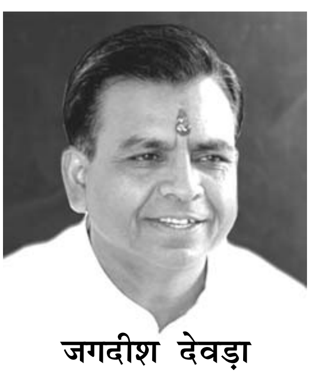
जगदीश देवड़ा

ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं नरेन्द्र सिंह तोमर

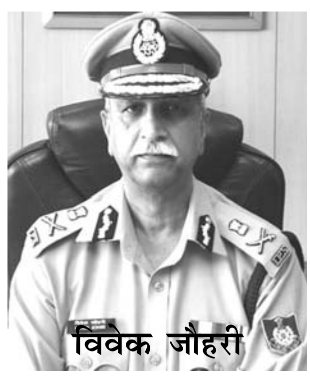
विवेक जौहरी

सुनील पाण्डेय

ज्यादा मामलों में ऐसी उठापटक हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजरों में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा किस कदर चढ़े हुए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, एडीजी प्रशासन व इंटेलिजेंस के तमाम आग्रह के बावजूद सुनील पांडे मंदसौर के एसपी के रूप में बरकरार नहीं रह पाए। दरअसल, मंदसौर जिले के बाकी जनप्रतिनिधि तो पांडे से खुश थे, लेकिन देवड़ा से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। देवड़ा ने जब मुख्यमंत्री के सामने अपना दुखड़ा रोया तो उन्होंने बिना किसी विलंब उन्हें वहां से हटाने का निर्णय अफसरों को यह कहते हुए ले लिया कि जिस एसपी की देवड़ा जैसे सीधे-सादे मंत्री से नहीं पट सकती, उसे वहां रहने का कोई हक नहीं। वैसे संबंध बिगड़ने का एक बड़ा कारण पांडे द्वारा एसपी रहते हुए एक बड़े अफीम तस्कर पर हाथ डालना भी बताया जा रहा है।

लक्ष्मण सिंह मरकाम इन दिनों बड़ी चर्चा में हैं। मूलत: नौसेना के अधिकारी मरकाम इन दिनों मध्यप्रदेश सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और आदिवासियों से जुड़े मामले में सरकार के मुख्य मार्गदर्शक

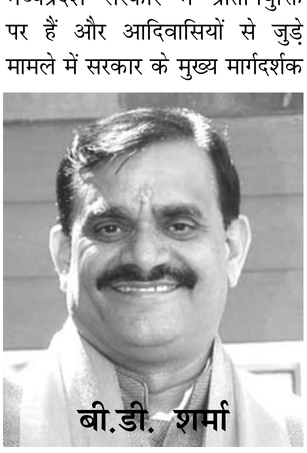
बी.डी. शर्मा

लक्ष्मण सिंह मरकाम

हैं। संघ की मजबूत पृष्ठभूमि मरकाम का सकारात्मक पक्ष है। ऐसा माना जा रहा है कि चाहे वह मध्यप्रदेश के आदिवासी कलाकारों को पद्मश्री की अनुशंसा का मामला हो या फिर आदिवासी छात्र-छात्राओं से जुड़ा मुद्दा, मरकाम से जो फीडबैक मिलता है, उसी आधार पर सरकार रणनीति बनाती है। प्रदेश के 4 आदिवासी सांसदों गुमान सिंह डामोर, गजेन्द्र पटेल, प्रो. सुमेर सिंह सोलंकी और

अजय तिर्की

दुर्गादास उइके को आगे कर मरकाम आदिवासी बहुल जिलों में जयस, भारतीय ट्राइबल पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किले में सेंध लगाने की तैयारी में भी लगे हैं। लक्ष्य अगले विधानसभा चुनाव के पहले इन क्षेत्रों में भाजपा का आध ार मजबूत करना है। प्रदेश के मुख्य सचिव का फैसला होने में तो अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अनुराग जैन भी मुख्य सचिव हो सकते हैं, इस चर्चा ने इंदौर में उनकी बहन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. रेणु जैन को मजबूत कर रखा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जमीन से जुड़े एक मामले में आखिरकार जैसा डॉ.

अनुराग जैन

जैन चाह रही थीं, वैसा ही हुआ और वह भी उन्हीं के कुलपति कक्ष में इंदौर के कलेक्टर और निगमायुक्त की मौजूदगी में। कहा यह जा रहा है कि अभी जब केवल जैन के मुख्य सचिव बनने की चर्चा ने ही डॉक्टर जैन को इतना वजनदार बना रखा है तो फिर उनके मुख्य सचिव बनने की स्थिति में आगे क्या होगा, यह समझना भी जरूरी है। सीनियर आईएएस अफसर अजय तिर्की और

के.सी. गुप्ता

के.सी. गुप्ता के केंद्र से वापसी के बाद मध्यप्रदेश में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव संभावित है। इस बदलाव में वे आईएएस अफसर भी महत्वपूर्ण पदस्थापना पा सकते हैं, जो पिछले दिनों सचिव से प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नत हुए। वे तमाम प्रमुख सचिव भी इस फेरबदल में प्रभावित हो सकते हैं, जो इन दिनों दोहरी भूमिका में हैं। इनमें से कुछ का वजन कम होना तय है। देखते हैं किसे फायदा होता है और कौन नुकसान में रहता है? यदि कोई अधिकारी अपने सेवाकाल में अपने सहयोगियों के वेलफेयर के लिए चिंतित रहता है तो सहयोगी भी उन्हें

डॉ० रेणु जैन

कभी भुला नहीं पाते हैं। भोपाल का एस.पी. रहते हुए पुलिसकर्मियों के लिए कॉलोनी विकसित करने वाले आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंह की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए संजीव नगर के रहवासियों ने कॉलोनी परिसर में ही उनकी मूर्ति स्थापित कर दी है। इस प्रतिमा का अनावरण भी रहवासियों ने संजीव सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के हाथों ही करवाया। इस मौके पर अनेक पुलिस अधिकारी और राजनेता मौजूद थे। सिंह का सालभर पहले बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती रहते हुए पांव फिसल जाने से निधन हो गया था। कमलनाथ यदि कांग्रेस के किसी नेता से नाराज हो जाएं तो फिर उसकी हालत खराब होना तय है। महिला कांग्रेस की नियुक्तियों के बाद कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना अर्चना जायसवाल को करना पड़ रहा है। इन दिनों उनकी आवाजाही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर बंद-सी हो गई है। जब भी भाजपा या संघ के लिए धन संग्रह की नौबत आती है, तो उन तमाम नेताओं से जो विधायक या निगम-मंडलों में पदाधिकारी रहने के बाद लगभग भुला-से दिए गए हैं, सबसे पहले मदद मांगी जाती है। सालों पहले

सुहास भगत

अर्चना जायसवाल

कमलनाथ

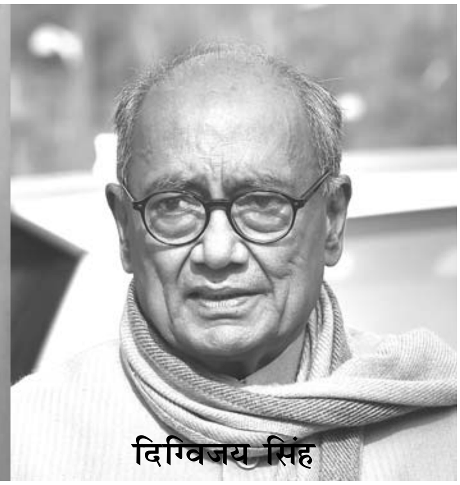
दिग्विजय सिंह

विधायक रहे इंदौर के 2 नेता तो इस मामले में अपना दुखड़ा सार्वजनिक तौर पर सुनाने लगे हैं। इनका कहना है कि यूं तो हमें कोई पूछता नहीं लेकिन पैसा लेने सबसे पहले आते हैं।

गौरतलब हो कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इलेक्शन मोड में आ गए हैं। जिस अंदाज में वे इन दिनों अफसरों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी खिंचाई करने में पीछे नहीं रह रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वे जनता के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए सबकुछ आप ही हो। फील्ड के अफसरों चाहे वे कमिश्नर हों या आईजी, कलेक्टर हों या एसपी से वे जब भी बात करते हैं, यह जताने में पीछे नहीं रहते हैं कि यदि उनके मातहत अमले ने जनता के साथ लापरवाही की तो उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। इसी का नतीजा है कि ये आला अफसर बेहद चौकन्ने हैं और अपने मातहतों की लगाम कसे हुए हैं। वही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में वी.डी. शर्मा ने दो साल पूरे कर लिए। शर्मा की गिनती अब उन अध्यक्षों में होने लगी है, जिन्होंने प्रदेश में बूथ स्तर पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। कहने वाले भले ही यह कहें कि शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच पटरी नहीं बैठ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ने अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है और एक-दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। न चाहते हुए भी दोनों अनमने ढंग से उन निर्णयों को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें एक-दूसरे की रुचि रहती है। यही कारण है कि दोनों के समर्थक भी खुश हैं और जमकर उपकृत हो रहे हैं। दिगर बात हो कि दूसरी तरफ कमलनाथ के पंच प्यारों की इन दिनों बड़ी चर्चा है। खरगोन विधायक रवि जोशी, देपालपुर के विधायक विशाल पटेल, बैतूल के विधायक निलय डागा, इंदौर के विधायक संजय शुक्ला और ग्वालियर के विधायक प्रवीण पाठक इन दिनों पूरे प्रदेश में कमलनाथ के नेटवर्क को मजबूत करने में लगे हैं। कमलनाथ जब भोपाल में रहते हैं, तब इन लोगों का मुकाम भी 9, श्यामला हिल्स पर ही रहता है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। इन पंच प्यारों का कमलनाथ के प्रिय पात्र दो दिग्गज नेताओं सज्जन सिंह वर्मा और एन.पी. प्रजापति से भी बहुत अच्छा तालमेल है।

रवी जोशी

विशाल पटेल

निलय डागा

संजय शुक्ला

प्रवीण पाठक

वही बताते चले कि दिग्विजय सिंह की खरी-खरी इन दिनों बड़ी चर्चा में है। सैलाना के कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन गहलोत के परिवार में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह जावरा के कांग्रेस नेताओं के दो समूहों के सामने जो कुछ बोले उससे तो यह संकेत मिल रहा है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस यदि इस बार चुनाव नहीं जीती तो फिर उसकी हालत भी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस की है, वैसी ही होना तय है। कार्यकर्ताओं के सामने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए दिग्विजय ने खुद की असहायता तो दिखाई ही साथ ही लगे हाथों यह भी कह दिया कि ऐसी स्थिति में कमलनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 'राजा' तो बोल गए अब सोचने का

एन.पी. प्रजापति

सज्जन सिंह वर्मा

विषय कमलनाथ के लिए है।

सनद् रहे कि प्रदेश के नए डीजीपी के लिए अफसरों के नामों का पैनल भेजने में विलंब क्या हुआ, यह चर्चा जोरों पर चल पड़ी कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अपने मित्र और मई में रिटायर हो रहे आईपीएस अफसर राजीव टंडन को दो-चार महीने के लिए इस पद पर देखना चाहते हैं। अपने प्रदेश का डीजीपी बनना हर आईपीएस अफसर की ख्वाहिश होती है और ऐसे में

अमनवीर सिंह बैंस

यदि कोई मददगार बन जाए तो फिर क्या कहना। ऐसी अटकलें हैं कि सेवानिवृत्ति के पहले टंडन तीन माह के लिए प्रभारी डीजीपी की भूमिका में आ जाएंगे। वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी मार्च के शुरुआत में रिटायर

सोमेश मिश्रा

हो रहे हैं। बैंस और टंडन दोनों गुना में साथ-साथ कलेक्टर और एसपी रह चुके हैं। वही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बेटे अमनवीर सिंह बैंस बैतूल के कलेक्टर हैं और गृह विभाग के प्रमुख सचिव रहने के बाद भिंड से सांसद रहे रिटायर आईएएस अधिकारी भागीरथ प्रसाद की बेटी सिमाला प्रसाद वहां एसपी हैं, लेकिन

इकबाल सिंह बैंस

राजीव टंडन

दोनों के बीच इन दिनों पटरी नहीं बैठ रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की बेतूल यात्रा के पहले दोनों के बीच तालमेल के अभाव में जो स्थिति निर्मित हुई, उसके चलते मुख्यमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और एस.पी. अफसरों के निशाने पर आ गईं। वैसे सिमाला की छवि साफ-सुथरी और सख्त अधिकारी की है, लेकिन अपने जिले से संबंधित एक मामले में कलेक्टर को विश्वास में न लेना उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। सनद् रहे कि उच्च पदों पर बैठे अफसरों की सक्रियता कई बार सरकार की परेशानी कम कर देती है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मौके आए, जब गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सरकार के संकटमोचक बने। मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुंडेर धंसने से लोगों के कुएं में गिरने का मामला हो या फिर कटनी के नजदीक स्लीमाबाद में नौ लोगों के टनल में फंसने की घटना। दोनों मामलों में डॉ. राजौरा मुख्यमंत्री को तो पल-पल की जानकारी देते ही रहे, साथ ही ग्राउंड लेवल से जो अपडेट मिल रहे थे, उसे अनवरत मीडिया से शेयर करते रहे। इसी का नतीजा था कि चाहे अखबार हो, चैनल हो या फिर सोशल मीडिया, किसी भी माध्यम से जानकारी के अभाव में घटनाओं का अतिरंजित स्वरूप सामने नहीं आया।

डॉ० राजेश राजौरा

झाबुआ के कलेक्टर युवा आईएएस अफसर सोमेश मिश्रा इन दिनों नौकरशाही के निशाने पर हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तो पिछले दिनों उनसे अपनी नाराजगी का इजहार

सिमाला प्रसाद

कुछ अलग तरीके से कर ही चुके हैं। मिश्रा की झाबुआ में अतिसक्रियता भी इन दिनों बड़ी चर्चा है। बेहद मुखर रहने वाले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा परेशानी में आ गए हैं। भाजपा की इंदौर शहर इकाई

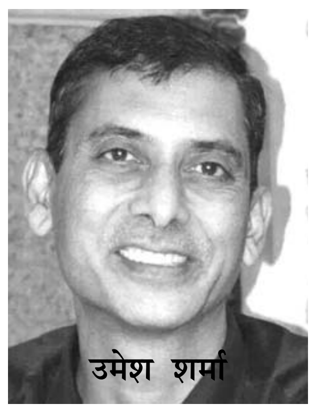
उमेश शर्मा

में एक नियुक्ति के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में मुंह खोला, उससे विरोधियों को आखिरकार मौका मिल ही गया। देखना यह है कि प्रदेश संगठन महामंत्री के प्रिय पात्र नगर अध्यक्ष पर शाब्दिक वार करने वाले शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बख्शते हैं या फिर कोई कड़ा निर्णय लेते हैं।

नीरा

पौष्टिक प्राकृतिक पेय भी, गुणकारी औषधि भी

● **ललन कुमार प्रसाद**

ताड़ और खजूर के पेड़ हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश के अधिकतर भागों में सदियों से पाया जाता रहा है। इस धरती पर ताड़ और खजूर को मिठास का पहला स्त्रोत माना गया है। इतना ही नहीं, इनके पेड़ों के सभी भागों का व्यवहार लाभकारी है। इसलिए ताड़ को कल्पवृक्ष यानि 'ट्री ऑफ लाइफ' की संज्ञा दी गई है।

✮ **नीरा क्या है? :-** सूर्योदय के पहले ताड़ और खजूर के पेड़ों से रातभर के स्रावित रस को संग्रहित करके रखे गये तरल पदार्थ को नीरा कहते हैं। इस प्राकृतिक पेय को पीने से नशा नहीं चढ़ता है यानि आदमी मदहोश नहीं होता है। इसमें सुपाच्य शर्कराओं यानि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और खनिज लवणों की प्रचूरता होती है। इसलिए यह पीने में मीठा और स्वादिष्ट लगता है। अत: प्रात:काल चाय के स्थान पर एक ग्लास नीरा पी लिया जाये तो नाश्ते के अतिरिक्त अन्य पदार्थ खाने की जरूरत नहीं रहती है। सुबह सवेरे इसको पीने से ताजगी और प्रसन्नता आती है। यह बहुत ही सस्ता और सुलभ है। इसलिए गांव और कस्बों के गरीब लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं। सूर्योदय के बाद ताड़ और खजूर से स्रावित इसी संग्रहित रस का किण्वन (फरमेंटेंशन) होने के चलते ताड़ी में तब्दील हो जाता है। ताड़ी पीने से नशा चढ़ता है और आदमी बदहोश हो जाता है। अर्थात् इंसान से हैवान में तब्दील हो जाता है। जाहिर है जब आदमी होश खो देगा यानि होश में नहीं रहेगा तो शैतान हो ही जायेगा।

✮ **नीरा और ताड़ी में अंतर :-**

☞ ताड़ और खजूर के ताजे रस नीरा को कहते हैं। लेकिन सूर्योदय के बाद इसे मुक्त हवा में छोड़ देते हैं तो इसमें स्वत: खमीरीकरण या किण्वन होने के चलते गैस निकलने लगती है और झाग बनने लगता है। जिससे नीरा कुछ देर बाद ताड़ी में परिवर्तित हो जाता है।

☞ नीरा पीने से जरा भी नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन ताड़ी पीने से नशा चढ़ता है। क्योंकि खमीकरण के चलते इसमें लगभग

4% अल्कोहल पैदा हो जाता है। परन्तु ताड़ या खजूर के ताजा रस में पुरानी ताड़ी की गाद खमीर के रूप में मिला दिया जाये तो खमीरीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे ताड़ी में अल्कोहल की मात्रा 4% से काफी अधिक हो जाती है। गांव और कस्बे की गरीब जनता इसी ताड़ी को मादक पेय के रूप में सेवन करती है।

☞ नीरा स्वाद में मीठा और स्वादिष्ट होता है जबकि ताड़ी खट्टी तथा बेस्वाद होती है। ताड़ी पीने में जरा भी मजा नहीं आता है, लेकिन नशा जरूर चढ़ता है।

☞ ताड़ी के मुकाबले नीरा पीने में जीवनोपयोगी तत्व अधिक होते हैं।

☞ नीरा मादक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है जबकि ताड़ी मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है।

✮ **नीरा के पोषक तत्व :-** नीरा में जल 84.72%, कार्बोहाइड्रेट 14.35%, प्रोटीन 0.32%, वसा 0.17% और खनीज-लवण 0.86% होता है। खनीज-लवण के रूप में आयरन 0.15% और फॉस्फोरस 0.67% होता है। कैल्सियम, फॉस्फोरस और सोडियम भी पर्याप्त मात्रा में

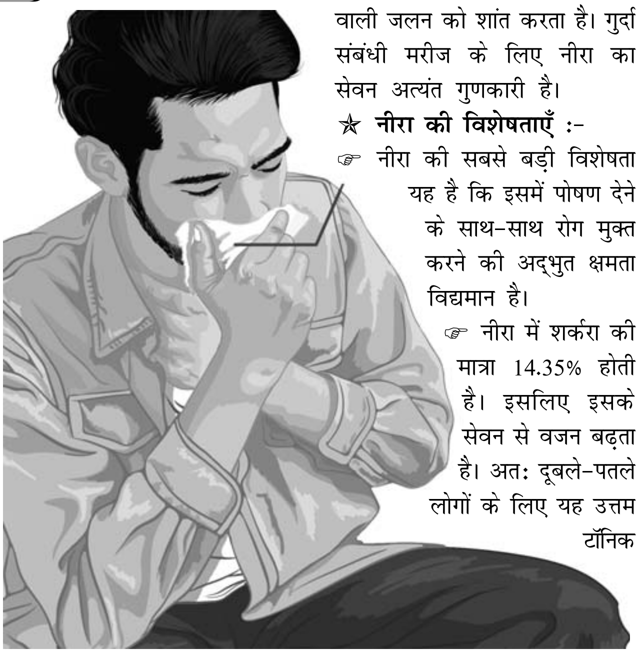

विद्यमान रहता है। इसमें विटामिन सी यानि स्कॉर्बिक एसिड 0.18-0.30%, साइट्रिक एसिड 0.50% और विटामिन डी कॉम्पलेक्स प्रचूरता में रहता है। इसके प्रति 100 मिली लीटर से 110 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।

✯ **नीरा के औषधीय गुण :-** नीरा पीने से पाचक रस की वृद्धि होने के साथ कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसलिए इसके सेवन से उदर संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। नीरा के सेवन से हेमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। इसलिए खून की कमी वाले मरीजों के लिए इसका सेवन गुणकारी है। यह पीलिया की अति उत्तम दवा मानी जाती है। यह मूत्रल है और मूत्र मार्ग में पायी जाने वाली जलन को शांत करता है। गुर्दा संबंधी मरीज के लिए नीरा का सेवन अत्यंत गुणकारी है।

✯ **नीरा की विशेषताएँ :-**

☞ नीरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पोषण देने के साथ-साथ रोग मुक्त करने की अद्‌भुत क्षमता विद्यमान है।

☞ नीरा में शर्करा की मात्रा 14.35% होती है। इसलिए इसके सेवन से वजन बढ़ता है। अत: दूबले-पतले लोगों के लिए यह उत्तम टॉनिक है।

☞ नीरा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 14.35% और गन्ने के रस में 21.8% होती है। इसलिए नीरा का सेवन मधुमेह के मरीजों के लिए सुरक्षित है जबकि गन्ने के रस का सेवन सुरक्षित नहीं है।

☞ नीरा में फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक 0.6% होती है। इसलिए इसके सेवन से बच्चों के दिमाग तेज हो जाते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए यह अतिउत्तम दवा है। नीरा इतना पौष्टिक होता है कि सुबह-सुबह दूध की जगह एक ग्लास नीरा बच्चों को पिला दिया जाये तो उसकी आम खुराक में किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी नहीं रह जाती है। इसके सेवन से बच्चों की बुद्धि निखरने के साथ-साथ उनके वजन और लम्बाई दोनो में भी वृद्धि होती है।

☞ प्रात: काल नीरा पीने से न केवल छोटी आंत की कृमि निकलती है, बल्कि पुन: पैदा होने से रूकती भी है।

☞ गर्भवती स्त्रियों द्वारा नीरा का सेवन करने से न केवल पैदा होने वाले बच्चे का रंग बहुत साफ होता है, बल्कि बच्चा होने के बाद जच्चा-बच्चा दोनो का स्वास्थ भी ठीक रहता है।

☞ यह खमीर और विटामिन बी. कम्पलेक्स का उत्तम स्त्रोत है।

✯ **नीरा : चित भी मेरी पट भी मेरी :-** यह यक्ष्मा या तपेदिक या क्षयरोग यानि टी.बी. की सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवा है। वास्तविकता तो यह है कि नीरा या ताड़ी टी.बी. की बिल्कुल रामवाण दवा है। टी.बी. के मरीज इलाज हेतु इस्तेमाल में लायी जाने वाली जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं, सब के सब नीरा या ताड़ी के समक्ष बहुत ही बौनी सिद्ध हुई है। अपने समय के देश के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ एलोपैथिक चिकित्सक स्व० डॉ० घोषाल, जो पटना के मखनिया कुआं रोड में मरीजों का इलाज करते थे, ने बगैर कोई एलोपैथिक दवा खिलाये पटना और पूरे बिहार के टी.बी. के हजारों मरीजों को केवल नीरा या ताड़ी पिलाकर भला-चंगा कर दिये। उनके कथनानुसार सुबह-शाम नित्य दो-दो ग्लास नीरा या ताड़ी पीने से टी.बी. के मरीज महज दो महीने के अंदर पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। साथ ही दोबारा टी.बी. से संक्रमित होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। उनका कहना था कि ताड़ी के मुकाबले नीरा कुछ अधिक असरदार होता है।

✯ **ताड़ या खजूर के पेड़ से नीरा प्राप्त करने की विधि :-** ताड़ और खजूर के पेड़ से रस निकालने का काम पासी जाती के लोग करते हैं। वे उसके लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। पांव में रस्सी का फंदा लगाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। साथ ही कमर में बंधे बेल्ट के एक हूक में हसिया और दूसरे हूक में मिट्‌टी का एक पात्र, जिसे लबनी कहते हैं, लटका लेते हैं। फिर गुच्छानुमा पत्तेदार शिखर के ठीक नीचे तने की सतह पर हसिया से छिलाई करके अंग्रेजी के 'वी' अक्षर की आकृति बनाकर नीचे की ओर एक नलकी बना लेते हैं। नलकी के पास बांस की दो छोटी खूंटियां गांड़कर उन पर साथ में लगे लबनी को टांग देते हैं। रातभर लवनी में पेड़ से स्रावित रस चू-चूकर जमा होता रहता है। प्रात: सूर्योदय के आधा घंटा पहले लबनी में एकत्रित रस को उतार लेते हैं। इस कार्य को सूर्योदय के आधा घंटा पहले कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद संग्रहित किये गये रस में झाग आ जाने पर नीरा, ताड़ी में तब्दील हो जाता है तथा वह नीरा के मुकाबले कम

गुणकारी हो जाता है। ताड़ के एक परिपक्व पेड़ से प्रतिदिन 8-10 लीटर और खजूर के एक परिपक्व पेड़ से 2-3 लीटर तक नीरा प्राप्त होता है। पेड़ के जिस स्थान से एक बार नीरा निकाला जाता है, एक सप्ताह तक उसी स्थान से वही प्रक्रिया अपनाकर नीरा निकाला जाता है। लगातार एक सप्ताह तक रस निकालने के बाद स्थान बदल दिया जाता है।

✯ नीरा के सेवन से संबंधित सावधानियां :-

☞ सूर्योदय के पहले पेड़ से उतारने के बाद नीरा को पीने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीतते समय के साथ प्रचूर मात्रा में हवा की मौजूदगी में नीरा स्वत: ताड़ी में परिवर्तित होने लगता है।

☞ अल्कोहल की मौजूदगी के चलते सामान्य परिमाण में ताड़ी पीने से नशा होता है, लेकिन शराब जितना नहीं, परन्तु अधिक मात्रा में ताड़ी पीने से शराब जैसा ही नशा आता है। इसलिए सूर्योदय के पहले ताड़ या खजूर के पेड़ से उतारे गये रस या नीरा का सेवन सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिए, वरना वह रस खमीरीकरण के चलते ताड़ी बन जाता है। मादक पेय होने के कारण ताड़ी पीना निंदनीय है।

✯ नीरा को ताड़ी में परिवर्तित होने से रोकने के उपाय :-

☞ ताड़ और खजूर के पेड़ से स्रावित रस को संग्रहित करने के लिए नित्य शाम को सूर्यास्त के बाद साफ गर्म पानी से लबनी को अच्छी तरह से धोने के बाद पोटैशियम परमैंगनेट के जलीय घोल से भी धो लें और तब लबनी को पेड़ से टांगना चाहिए और तब नित्य सूर्योदय के आधा घंटा बाद स्रावित रस को पेड़ से उतार लेना चाहिए। लबनी को धोने के लिए आधा लीटर साफ पानी में आधा ग्राम (500 मिली ग्राम) पोटैशियम परमैंगनेट मिलाकर घोल तैयार करना चाहिए।

☞ नीरा को भंडारित करने वाले मिट्टी के पात्र को भी अच्छी तरह से साफ पानी से धोने के बाद पोटैशियम परमैंगनेट के घोल से ध ोना चाहिए और तब उसमें नीरा को भंडारित करना

चाहिए।

प्रचूर मात्रा में मुक्त हवा के सम्पर्क से बचाने के लिए मिट्टी के पात्र को मोटे किन्तु साफ कपड़े से अच्छी तरह बांधकर छांव में ठंडी जगह रखना चाहिए। ऐसा करने से बीतते समय के साथ नीरा के स्वत: ताड़ी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। साथ ही धूल और अन्य किसी भी प्रकार की गंदगी से दूषित होने से नीरा बच जाता है। मिट्टी के पात्र की भितरी सतह पर लगा पोटैशियम परमैंगनेट का घोल प्रीजरवेटिव का काम करता है। अर्थात् नीरा के खमीरीकरण को रोक देता है। लबनी के अंदर चूना का लेप लगा देने से भी नीरा, ताड़ी में जल्दी तब्दील नहीं होता है, लेकिन पोटैशियम परमैंगनेट का घोल पन्द्रह दिनों तक नीरा को ताड़ी में तब्दील होने से बचाता है। फिर लबनी के अंदर चूने का लेप लगाने की तुलना में पोटैशियम परमैंगनेट के घोल से धोना हर तरह से बेहतर होता है। पोटैशियम परमैंगनेट के घोल से धोने के चलते सूर्योदय के बाद भी जब लबनी में दिनभर नीरा स्रावित होता रहता है, लेकिन ताड़ी में तब्दील नहीं होता है।

☞ नीरा में ताड़ी या ताड़ी का गाद नहीं मिलाना चाहिए, वरना नीरा तेजी से ताड़ी में परिवर्तित होने लगता है।

✯ कानून बनाकर नीरा पीने के लिए प्रेरित करे सरकार :- ताड़ या खजूर के पेड़ से स्रावित रस को उतारने वाले अधिकांश पासी ताड़ के खुद मालिक नहीं होते हैं। मालिक वे होते हैं, जिनकी जमीन में ताड़ उगा होता है। ताड़ और खजूर के पेड़ बटाई की चीज है। इसलिए पेड़ के मालिकों को घर बैठे फायदा मिल जाता है। फिर भी बिहार सरकार को अविलंब कानून बनाकर तय कर देना चाहिए कि पेड़ से रस उतारने वाले और पेड़ के मालिक की हिस्सेदारी अलग-अलग कितनी हो, जिससे की किसी की हकमारी न होने पाये। सरकार को यह भी कानून बना देना चाहिए कि नीरा के उत्पादन का लाइसेंस उसी को मिले, जो ताड़ के पेड़ से रस उतारता हो। ताड़ी बेचने पर पाबंदी जरूर हो, लेकिन नीरा बेचने पर कोई पाबंदी न हो। नीरा को कही भी सूर्योदय के एक घंटा पहले से लेकर सूर्यास्त के एक घंटा बाद तक बेचा जा सके। इसे कही भी सड़क से हटकर पेड़ के नीचे खुले में या झोपड़ी में बेचे जाने की इजाजत हो। लेकिन जहां भी बेचा जाये, वह जगह साफ-सुथरा जरूर हो तथा स्कूल-कॉलेज के समीप न हो।

✯ आसान नहीं है ताड़ी पीने की लत से मुक्ति दिलाना :- प्रश्न उठता है कि दलित, खासकर मुसहर जाति के लोग ताड़ी पीने के लिए इतने लालायित क्यों रहते हैं? पहली बात की ज्यादातर मूसहर या अन्य दलित लोग बहुत ही गरीब व अनपढ़ हैं। उनके पास अपना जमीन नहीं होता है। दूसरे के खेतों में हल चलाकर, कुदाल चलाकर, रोपणी करके, तैयार फसलों की कटाई करके, निरायी-गोरायी करके, तैयार हो रही फसलों के बीच से खर-पतवार निकालकर, तैयार कटे हुए फसलों

का गट्ठर बनाकर, फसलों के गठरों कों खेत से खलियान तक ढ़ोकर ले जाने का काम करके गुजर-बसर करने के लिए मेहनत-मजदूरी करते हैं। सुबह से शाम तक जीतोड़ मेहनत करने के चलते शाम होते-होते थककर चूर हो जाते हैं। इसलिए थकान मिटाने के लिए मादक पदार्थ के रूप में ताड़ी का सेवन करते हैं। ताड़ी गांव और कस्बों में हर जगह आसानी से उपलब्ध होने वाला बहु ही सस्ता मादक पेय है। विशेषकर मुसहर और थारू जाति के लोगों का यह बहुत ही पसंदीदा पेय है। अब प्रश्न उठता है कि मूसहर शारीरिक रूप से बलिस्ट कैसे होते हैं, जबकि उनको भरपेट भोजन का लाला पड़ा रहता है। इसलिए उनके भोजन में पौष्टिक तत्वों का भारी आभाव होता है। बात यह है कि ताड़ी एक बहुत ही पौष्टिक प्राकृतिक पेय है। यह उनके लिए अतिउत्तम टॉनिक का काम करता है। यह उत्तम औषधि के रूप में भी उन्हें बीमारियों के हमले से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

पूर्वी चम्पारण में बुढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा मेहसी नामक एक स्थान है, जहां सीप के बटन तथा सीप के बने रंग-बिरंगे खूबसूरत व आकर्षक खिलौने बनाये जाते हैं। मेहसी में बने दिल को मोह लेने वाले सीप के खिलौनों का देश-विदेश में भारी मांग है। इन खिलौनों का अच्छी-खासी मात्रा में निर्यात किया जाये तो देश को विदेशी मुद्रा की अच्छी-खासी कमायी हो सकती है। सीप बूढ़ी गंडक यानि सिकरहना नदी में बहुतायत में पाया

जाता है।

मेहसी स्थित सीप उद्योग में भारी मात्रा में सीप की जरूरत पड़ती है। जिसे वहां रहने वाले मुसहर जाति के लोग उपलब्ध कराते हैं। नदी से सीप निकालना बहुत ही दमखम का काम है, जिसे सिर्फ और मुसहर जाति के लोग ही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे किसी भी जाति के लोगों के लिए इतने अधिक दमखम का काम करना संभव नहीं है। अत्याधिक गरीब होने के चलते मुसहर जाति के लोगों को खाने के लाले पड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें पौष्टिक भोजन नसीब नहीं हो पाता है। वे लोग नदी से निकाले गये घोंघा और सीप के मांस का सेवन करते हैं, जो अत्यधिक पौष्टिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। इसलिए मुसहर लोग शारीरिक रूप से बहुत अधिक बलिष्ट होते हैं। घोंघा और सीप का मांस उन्हें बीमारियों के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। कोरोना का वायरस भी उन्हें संक्रमित करने में सफल नहीं हो पाया है।

मुंह-नाक पर गमछा लपेटकर काम करने के दौरान सीप उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के शरीर में कुछ न कुछ मात्रा में शीप के धूल प्रवेश कर जाते हैं, जो कई खतरनाक बीमारियों की रामवाण दवा है। मसलन टी.बी. से ग्रस्त कोई मजदूर लगातार दो महीने तक सीप के कारखाने में काम करता रहे तो उसे टी.बी. के बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात् वह भला चंगा हो जाता है।

मुसहर जाति के लोगों में ताड़ी पीने की लत सदियों पुरानी है। गांव-कस्बों के बूढ़े आदमी कहते हैं कि जब वह छोट बच्चे थे, उस

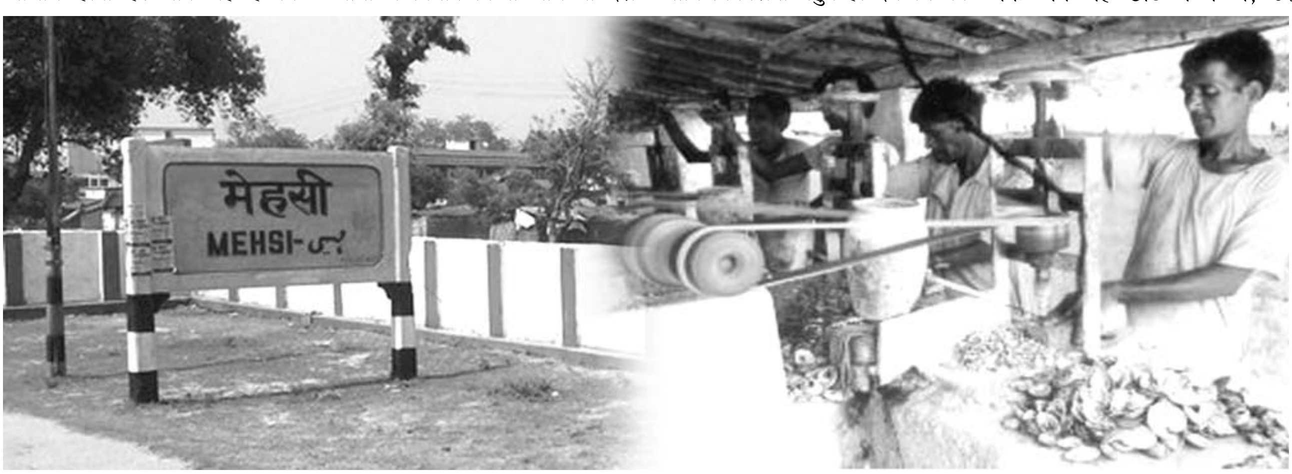

समय भी मुसहर तथा अन्य दलित लोगों को ताड़ के पेड़ के नीचे जमीन पर या टूटी-फूटी झोपड़ी में बैठकर ताड़ी पीते देखते थे। इसलिए सदियों पुरानी ताड़ी पीने की लत से उन्हें मुक्ति दिलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बिहार सरकार को ताड़ी की जगह सेवन करने हेतु प्रेरित करने के लिए जमीनी स्तर पर जमकर काम करना होगा।

✯ शराब और ताड़ी : एक तुलनात्मक अध्ययन :- शराब और ताड़ी, दोनो ही मादक पदार्थ है। क्योंकि दोनो के सेवन से नशा चढ़ता है। फिर भी दोनो में आकाश-पाताल का अंतर है :-

☞ शराब मैनमेड मादक पेय है अर्थात् यह एक कृत्रिम मादक पेय है। लेकिन नीरा को ताड़ी में तब्दील करने के लिए जरा सी भी कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह अपने आप ही ताड़ी में तब्दील हो जाता है। अर्थात् ताड़ी प्राकृतिक मादक पेय है। नीरा, ताड़ी में तब्दील न हो इसके लिए जरूरी है कि नीरा में नगन्य मात्रा में कोई प्रीजरवेटिव केमिकल मिला दिया जाये।

☞ शराब काफी मंहगा मादक पेय है, जबकि ताड़ी अत्यधिक सस्ता मादक पेय है।

☞ शराब का सेवन सामान्यत: पैसा वाले सिर्फ और सिर्फ नशा और अय्यासी के लिए करते हैं जबकि ताड़ी का सेवन गरीब लोग थकान मिटाने के लिए करते हैं।

☞ शराब का सेवन सेहत के लिए हर तरह से नुकसानदेह है जबकि ताड़ी का सेवन हर तरह से लाभकारी, सिर्फ नशा चढ़ने की खराबी को छोड़कर।

✯ आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है नीरा और नीरा के खाद्य व ताड़ के अखाद्य पदार्थ :- बिहार में नीरा उत्पादन और नीरा प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना अप्रैल 2016 में की गई। उसी वर्ष बिहार सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल 90 लाख 19 हजार ताड़ के पेड़ और कुल 40 लाख खजूर के पेड़ थे। गिनती के अनुसार बिहार राज्य के 8405 पंचायतों के 42 हजार 334 गांवों में ताड़ के कुल 90 लाख 12 हजार 480 पेड़ थे और खजूर के कुल 38 लाख 4 हजार 539 पेड़ थे। गया, नवादा, नालंदा, बांका, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और जहानाबाद जिलों में ताड़ के ज्यादा पेड़ थे। सबसे ज्यादा गया जिला में 14 लाख 57 हजार 410 पेड़, नवादा जिला में 8 लाख 65 हजार 97 पेड़, बांका जिला में 6 लाख 37 हजार 886 पेड़, भागलपुर जिले में 5 लाख 8 हजार 245 पेड़ और मुजफ्फरपुर जिला में 3 लाख 99 हजार 877 पेड़ थे। सबसे ज्यादा खजूर के पेड़ वाले जिले थे-बांका में 5 लाख 92 हजार 130 पेड़, मुजफ्फरपुर में 5 लाख 51 हजार 370 पेड़, समस्तीपुर में 4 लाख 5 हजार 662 पेड़ और गया में 3 लाख 53 हजार 37 पेड़ और दरभंगा में 2 लाख 9 हजार पेड़ थे।

✯ नीरा के खाद्य उत्पाद :- नीरा सेवन के फायदे तो जगजाहिर हैं, लेकिन इसके खाद्य उत्पादों की अहमियत भी कोई कम नहीं है। नीरा के प्रमुख खाद्य उत्पाद हैं-गुड़ और मिठाइयां।

✯ गुड़ :- नीरा संग्रहण के बाद उसये धातु के साथ बर्तन में अच्छी तरह उबालना चाहिए। जब नीरा उबलने लगे तो उबलने के दौरान उसमें पांच से छ: बार थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालें। ऐसा करने से नीरा में मौजूद गंदगी झाग के रूप में निकलकर सतह पर आ जाती है, जिसे छनौटा से निकालकर फेंक दें। नीरा को सुनहरे रंग का होने तक उबलने दे और तब उसे मनचाहे आकार व आकृति के धातु के बर्तन में उरेलकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। लीजिए गुड़ तैयार हो गया। प्रति किलोग्राम गुड़ तैयार करने के लिए 7-8 लीटर नीरा की आवश्यकता होती है। बहुत ही उम्दा, स्वादिष्ट और गुणकारी होने के चलते बाजार में ताड़ और खजूर से बने गुड़ की भारी मांग है। यह गुड़ इतना अच्छा

होता है कि इसे विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि ताड़ और खजूर से गुड़ निर्माण को लघु और कुटिर उद्योग के रूप में बढ़ावा दिये।

✯ **मिठाइयां :-** ताड़ और खजूर के गुड़ से पेड़ा, लड्डू आदि विभिन्न प्रकार की उम्दा मिठाइयां बनायी जाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। आइसक्रीम और पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक लोकप्रिय मिठाई संदेश भी इससे बनायी जाती है। बाजार में उपरोक्त मिठाइयों की भारी मांग है।

✯ **ताड़ और खजूर के अखाद्य उत्पाद :-** ताड़ और खजूर के पत्तों से विभिन्न प्रकार के सुंदर, आकर्षक और मनमोहक रंग-बिरंगे खिलौने बनाये जाते हैं। सखुआ, शीशम और सागवान की लकड़ियों की तरह ताड़ और खजूर की लकड़ी भी काफी मजबूत और टिकाऊ होती है। यही कारण है कि गांवों और कस्बों के खपड़पोश मकानों के शहतीह और छत के फ्रेम ताड़ और खजूर की लकड़ के बने होते हैं।

सर्वप्रथम ताड़ व खजूर के पेड़ से नीरा का संग्रहण किया जाता है। फरवरी-मार्च के महीने में ताड़ और खजूर के पेड़ों से रस का स्राव कम होता है। धीरे-धीरे रस के स्राव की मात्रा बढ़ती चली जाती है और अप्रैल-मई पहुंचते-पहुंचते अधिकत्तम हो जाती है। जिस तरह मुजफ्फरपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों की लीची स्वाद और गुणवत्ता में देश की सबसे अच्छी लीची होती है, यह उपरोक्त इलाके की मिट्टी और जलवायु की देन है। ठीक उसी तरह बिहार की मिट्टी और जलवायु ऐसी है कि यहां के ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से नीरा का स्राव अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला होता है। ऐसा चेन्नई स्थित कृषि विश्व विद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है। यही कारण है कि ताड़ और खजूर के गुड़ से बनी मिठाइयां गन्ने से प्राप्त चिनी की बनी मिठाइयों की तुलना में स्वाद और गुणवत्ता, दोनों में बेहतर होती हैं। इसलिए पूरे देश के बाजार में ताड़ और खजूर के गुड़ से बनी मिठाइयां अधिक कीमत में बिकती हैं। ताड़ और खजूर के गुड़ की भारी मांग है, लेकिन आपूर्ति अत्यधिक कम है। हमारे राज्य में खेतों के मेड़ों पर ताड़ और खजूर के पेड़ उगाकर वर्तमान के मुकाबले दोगुना तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अर्थात् ताड़ के पेड़ 90 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 80 लाख और खजूर के पेड़ 40 लाख से बढ़ाकर 80 लाख किये जा सकते हैं और किया ही जाना चाहिए। ऐस करने से किसानों की आय काफी बढ़ जायेगी। वे समृद्ध व खुशहाल हो जायेंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब बिहार सरकारा इस मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर समुचित प्रयास करे।

वर्ष 2017 में हुए करार के तहत भागलपुर स्थित सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम डॉ० आफताब के नेतृत्व में 25 जुलाई 2017 को चेन्नई के दौरे पर गई और तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय में रहकर नीरा उत्पादन और नीरा प्रोसेसिंग की तकनीक का अध्ययन किया। साथ ही नीरा के उत्पाद के निर्यात को लेकर जरूरी जानकारी प्राप्त की। नीरा उत्पादन और नीरा प्रोसेसिंग तकनीक के हस्तांतरण के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय और तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय के बीच करार हुआ। उसी वर्ष हाजीपुर और बिहारशरीफ में दो-दो हजार लीटर की क्षमता वाला नीरा प्रोसेसिंग व नीरा बोटलिंग प्लांट लगाया गया। दोनो ही प्लांटों में सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों

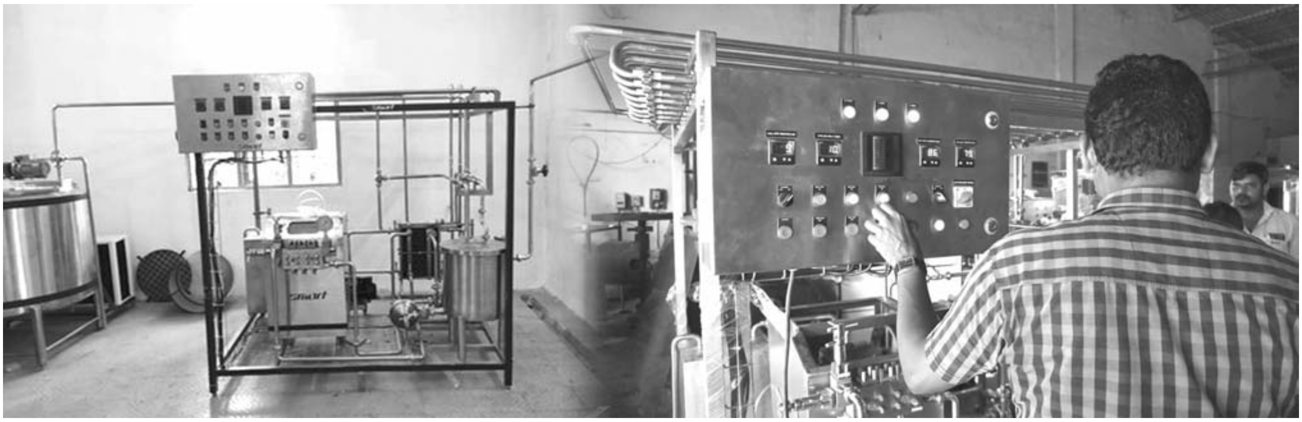

द्वारा बनायी गयी पाश्चुराइजेशन तकनीक के आधार पर नीरा का प्रसंस्करण किया जाने लगा, जो बाद में नीरा के खमीरीकरण के चलते उपयोगी नहीं रहा। ऐसा इसलिए कि खमीरीकरण के चलते नीरा में अल्कोहल बनने लगा। फलस्वरूप मद्य निषेध कानून लागू हो गया। नतीजा पिछले चार वर्षो से कॉम्फ्रेड में नीरा प्रोसेसिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। लेकिन 22 दिसम्बर 2021 को तमिलनाडू की सुभ्रथा देवी प्रोपराइटर इकोबाडी से सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। अब नीरा का प्रसंस्करण पाश्चुराइजेशन तकनीक से नहीं बल्कि स्टेरेलाइजेशन तकनीक से किया जायेगा ताकि नीरा का खमीरीकरण न होने पाये। यानि नीरा शराब में तब्दील न होने पाये। इस तकनीक के अपनाने से पन्द्रह दिनों तक नीरा का खमीरीकरण नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 दिसम्बर 2021 को घोषणा किया कि नीरा के व्यवसाय में लगे लोगों के जीवनोपार्जन योजना के तहत एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। साथ ही सात महीने तक एक-एक हजार रूपये भी दिये जायेंगे।

बात यह है कि पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार सरकार नीरा के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश में जुट गई है। नीरा परियोजना को लागू करने का मूल मकसद ही ताड़ और खजूर के पेड़ों से नीरा उतारने के पेशे में लगे पासी समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। नीरा परियोजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कॉम्फेड और जीविका को मुख्य कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी की कवायद का ही असर है कि अबतक 32 हजार नीरा उतारने वालों का निबंधन किया जा चुका है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वकांक्षी योजना नीरा उत्पादन और नीरा प्रोसेसिंग उद्योग के द्वारा नीरा तथा नीरा से बने उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आगे आया है। आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार सक्सेना ने बताया है कि आयोग पासी समुदाय के लोगों को नीरा के साथ-साथ गुड़ और खजूर के पेड़ों के पत्तों से डेकोरेटिव आईटम और खिलौने बनाने की ट्रेनिंग भी देगा। आयोग पासी समुदाय के लोगों को पेड़ से नीरा उताराने के लिए हाइटेक उपकरण भी देगा। ताड़ औ खजूर के पेड़ों से फरवरी से जून तक पांच महीने तक नीरा की प्राप्ति होती है। इसलिए खादी ग्रामोद्योग आयोग पासी समुदाय को नीरा प्रसंस्करण के साथ-साथ ताड़ और खजूर के पत्तों से डेकोरेटिव आईटम और खिलौने बनाने की ट्रेनिंग भी देगा। जिससे कि पासी समुदाय के लोगों को सालोभर आमदनी होती रहे।

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।।

नीरा के संवर्द्धन को लेकर बिहार सरकार पिछले पांच साल से भी अधिक समय से कार्यरत्त है। इसको लेकर सरकार करोड़ों रूपये खर्च कर चुकी है, फिर भी सरकार सफल नहीं हो सकी है। ऐसा समयबद्ध तरीके से नीरा के संग्रहण और वितरण का कार्य नहीं होने के चलते हो रहा है। जो सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही और सुस्ती का परिणाम है। नतीजा नीरा उद्योग पटरी पर नहीं आ सका है। इसे लेकर बिहार विकासोन्मुख नहीं हो पा रहा है। यह समय और पैसा दोनो की बर्बादी है। नतीजा सरकार को नफा के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आज भी अधिकतर लोग नीरा की जगह ताड़ी का सेवन खुलेआम कर रहे हैं, कही कोई रोकटोक नहीं है, जो पूर्ण शराबबंदी का खुल्लमखुल्ला उलंघन है। ●

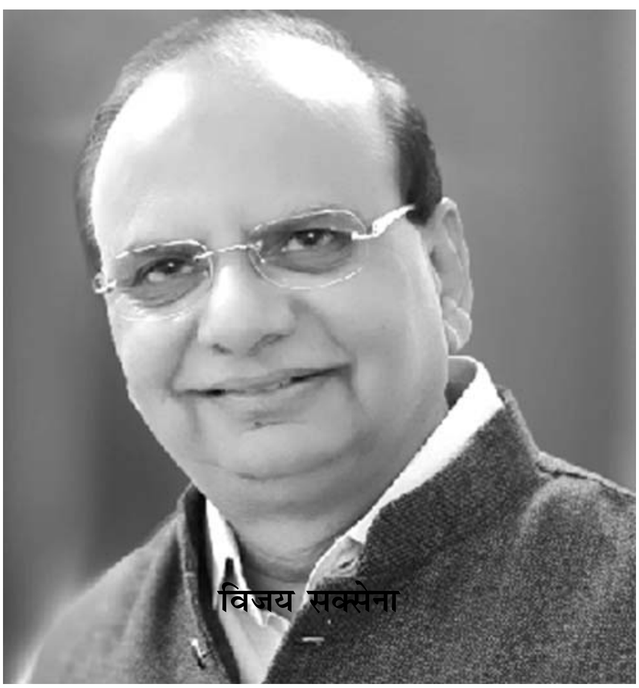

विजय सक्सेना

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)

मो०:- 9334107607

वेबसाईट www.psfsm.in

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485
7004408851

E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ पॉक्सो कानून क्या है? यह कब और क्यों लागू हुआ?

पॉक्सो का पूरा नाम "प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस" है, जिसका हिंदी में अर्थ लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण है। वर्तमान युग में मासूम एवं नाबालिग बच्चो के साथ रेप की घटनाये बढती जा रही है , लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे है, बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराधों की खबरें समाज को शर्मसार करती हैं, इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में यह विशेष कानून बनाया था, जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून से पहले भारत में यौन अपराधों के लिए कोई अलग से कानून नहीं था, इस कानून की खास बात यह है कि भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 के अंतर्गत केवल पुरुष ही बलात्कार का दोषी माना जाता था, लेकिन पॉक्सो एक्ट में लड़का और लड़की का अपराध समान माना गया है, और दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान की गयी है, अत: बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नाबालिक बच्चो की गोपनीयता के अधिकार का सम्मान किया जाये एवं सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे बालक के शारीरिक स्वास्थय, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सके।

✯ पॉक्सो कानून में अपराधो की सुनवाई किस प्रकार की जाती है?

पॉक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है, और इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्येश्य के लिए अनुवादक या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी होती है।

✯ पॉक्सो कानून में कौन से अपराध शामिल है और इन अपराधो के लिए कितनी सजा का प्रावधान है?

18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ किया गया किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के अन्तर्गत आता है, जिसके तहत नाबालिग बच्चों के साथ सेक्सुअल असाल्ट ,सेक्सुअल हेरास्मेंट, और पोर्न ग्राफी जैसे अपराध शामिल है, इन अपराधो से सुरक्षा के लिए इस कानून के तहत अलग- अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा और जुर्माना तय किया गया हैं।

पोक्सो कानून की मुख्य धाराए :- इस कानून के अंतर्गत किये गये अपराध सजा एवं जुर्माने का प्रावधान धारा 3 व 4 मे किया गया है। धारा 3 के के तहत प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी पार्ट में प्राइवेट पार्ट डालता है, या बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज डालता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है तथा बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है तो यह धारा-3 के तहत अपराध होगा। धारा 4 के अनुसार 7 साल से लेकर उम्रकेद की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6 धारा 6 के तहत उन मामलों को शामिल किया जाता है जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो या जिनमें बच्चो के साथ लैंगिक हमला किया गया हो, धारा 6 के अनुसार 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 7 व 8 :- धारा 7 के तहत उन मामलों को शामिल किया जाता है, जिसमें बच्चों के गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ की गई हो । धारा 8 के अनुसार इसमें दोष सिद्ध होने पर 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

धारा-11 व 12 :- धारा 11 के तहत उन सेक्सुअल हैरासमेंट को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों को गलत नियत छूता है या सेक्सुअल हरकतें करता है, अश्लील प्रयोजनों के लिए एक बच्चे को लुभाता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है। धारा 12 के अनुसार दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

✯ पॉक्सो में नये संसोधन के बाद क्या बदलाव हुए?

अप्रैल 2018 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन मामलों में सजा के प्रावधान और भी सख्त कर दिए गये है, जिसमें 12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। 2018 में किये गये संसोधन में 16 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में सजा 10 साल से बढाकर 20 साल कर दी गयी है। नए संसोधन के अनुसार पोक्सो के मामले में अब किसी दोषी व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) भी नहीं मिलेगी, दोषी व्यक्ति को सरेंडर करके जेल जाना होगा, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376, 376, 376 के अनुसार रेप मामले में बेल पर सुनवाई से पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीड़िता पक्ष को 15 दिन का नोटिस देना होगा।

✯ पॉक्सो के नए कानून में जांच व सुनवाई की समय सीमा कितनी होगी?

पॉक्सो के नए कानून में जांच व सुनवाई की समय सीमा तय कर दी गयी है जिसके तहत रेप के हर मामले की जांच किसी भी हाल में 2 महीने के अंदर पूरी की जाएगी, रेप मामलों की सुनवाई भी 2 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी, तथा रेप मामलों में अपील और अन्य सुनवाई के लिए अधिकतम छह महीने का वक्त दिया जाएगा।

✯ पॉक्सो कानून में हुए संसोधन के बाद यौन अपराधो पर कितनी रोक लगी है?

पॉक्सो के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के बहुत से मामले 2012 से 2016 के बीच दर्ज किये गए हैं, इसमें कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित पड़े हुए है जबकि अपराधी को सजा मिलने की दर बहुत कम है, जो कि अपराधों को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, हालाँकि सरकार के 2018 के संसोधन से किये गये बदलाव व फांसी की सजा के प्रावधान से इन अपराधो पर कुछ हद तक अंकुश लगा है, लेकिन सरकार को इस एक्ट में और जरूरी सुधार करने होंगे ताकि पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, लंबित मुकदमे और सजा की दर बताती है कि सिर्फ कानून बनाने से रेप के मामले नहीं रुकेंगे इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही भी तय करनी होगी, ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि बच्चों का शोषण जान-पहचान के लोग ज्यादा करते हैं, और घर के लोग उन पर शक भी नही करते हैं, और बच्चे डर के कारण ये बाते किसी से बता नहीं पाते और वे शोषण का शिकार हो जाते है, इसलिए माता- पिता का यह दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चो को जागरूक करे और इन सब अपराधो की जानकारी दे और जिन लोगों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, उन पर पूरी नजर रखें।

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

www.shruticommunicationtrust.org

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

Hotel Maurya – Patna is a pioneer project of **Bihar Hotels Limited (BHL).** It is the only **Five Star** category hotel in the State of Bihar with friendly face of affordable luxury. BHL has been successfully operating its Five Star Hotel in Patna since **1978.** Situated in the heart of the city, Patna, the hotel reflects the **historic grandeur** of this city.

Corporate Facilities & Services: Centrally located in the Commercial heart of Patna the Hotel provides Intricately & elegantly designed rooms, Central Air- Conditioning, Direct dialing from rooms with call detail print-out facility, Satellite LED television, Choice of **Seven Convention Halls** of varied capacities, **Heritage rooms** for private dining , **Business Centre, Shopping Arcade, Bank facility, Travel counter, Swimming pool, Safe deposit lockers, Fitness centre & Wi-fi**, all within the hotel premises.

Dining:

- *Vaishali Café* - Walk-in for Breakfast and Business Buffet Lunches. The a-la-carte table offers a multi cuisine and buffet spreads to tinkle those taste buds.
- *Spice Court* – Restaurant serving Indian, Continental, Thai & Chinese cuisine.
- *The Pastry Shop* – Provides all kinds of Baker's confectionery viz; Mouthwatering cakes, Crossiants, Breads, Muffins etc. It also provides free home delivery of cakes of 6 pound onwards.
- *Bollywood Treats*- A matchless meeting point for Munchies, Music, TV shows, Pool Table, Games for kids. Thus, providing Masti not only for adults but also for kids.

Rooms:

- Step into an universe of old world nobility & colonial charm at the spacious VVIP suite of rooms, where your every demand for luxury is met in a manner that's perfected to please. What's more, it's accommodating enough to entertain an entourage of guests. Elegantly designed premium rooms with beautiful interiors and excellent facilities

Total Rooms: 77 – Double: 73, Suites: 04

Credit Cards: Visa, Master, Amex, Bob Cards

Access (in kms): Apt: (07), Rly. Stn.:(01)